# इकाई 12 नागरिकता, शासन और प्रशासन*

## इकाई की रूपरेखा


12.0 उद्देश्य

12.1 प्रस्तावना

12.2 ब्राजीलः नागरिकता, शासन और प्रशासन

12.3 रूसः नागरिकता, शासन और प्रशासन

12.4 भारतः नागरिकता, शासन और प्रशासन

12.5 चीनः नागरिकता, शासन और प्रशासन

12.6 दक्षिण अफ्रीकाः नागरिकता, शासन और प्रशासन

12.7 निष्कर्ष

12.8 शब्दावली

12.9 संदर्भ लेख

12.10 बोध प्रश्न के उत्तर


## 12.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आपः


* डॉ मनन द्विवेदी, सहायक प्रोफेसर, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

- ब्रिक्स देशों की नागरिकता पर चर्चा कर सकेंगे, और
- ब्रिक्स देशों में शासन और प्रशासनिक व्यवस्था जान पाऐंगे।

## 12.1 प्रस्तावना

लोक प्रशासन शून्य में मौजूद नहीं है, क्योंकि इस शब्द का अर्थ यह बताता है कि यह केवल लोगों (नागरिकों) की देखभाल करता है और लोगों की सेवा करते समय यह संबंधित क्षेत्रों में प्रवेश कर सकता है। नागरिक प्रशासन संबंधों की घनिष्ठता गुणवत्ता और एक विशेषता को निर्धारित करती है, जो कि किसी भी राष्ट्र–राज्य में शासन और लोकतंत्र के विचार का आंतरिक भाग है। एक सच्चा नागरिक वह व्यक्ति होता है, जो अपने राष्ट्र–राज्य के विचार, देश के साथ अपनी संबद्धता और अपने राष्ट्र–राज्य में राष्ट्रवाद और शासन के विचार के साथ भावुक और भावुकतापूर्ण संबंध में विश्वास करता है, जो व्यक्ति देशभक्ति के पालन में विश्वास करता है और अपने कर्त्तव्यों को पूरी लगन से पूरा करता है, वह भी कुछ अधिकारों का हिस्सा बनने के लिए आगे बढ़ता है, क्योंकि अधिकारों और कर्त्तव्यों के मुद्दे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक नागरिक राष्ट्र–राज्य की मंडली की सबसे छोटी इकाई होता है, जहां से राष्ट्रीय निष्ठा की कहानी आरंभ होती हैं।

इस प्रकार, एक नागरिक को उदारवाद और सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के विचार में हॉब्स, लॉक और रूसो (Hobbes, Locke and Rousseau) जैसे दार्शनिकों द्वारा सामूहिकता के रूप में राष्ट्र–राज्य के विचार को बनाए रखने के लिए कुछ अधिकार

दिए गए है। इस प्रकार, नागरिकता में एक नए लोकतंत्र के फलने–फूलने के मूलभूत पहलू शामिल हैं, जिसमें शासन और न्याय के प्रशासन और देश के बड़े लोगों के लिए अच्छे शासन का विचार शामिल है।

जब अमीर और शक्तिशाली और औद्योगिक रूप से उन्नत राष्ट्रों की बात आती है, तो अन्य राष्ट्रों के सभी नागरिक प्रयास करते हैं और एक ऐसे राष्ट्र में प्रवास करते हैं, जो अवसर, विकास और आर्थिक प्रगति अर्जित करने वाला नया देश हो सकता है। ऐसा स्थल एक शैक्षिक स्थल, पर्यटन स्थल और ऐसी भूमि के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका होता है जिसके साथ व्यापार और व्यवसाय होता है। इस प्रकार, प्रत्येक राष्ट्र राष्ट्रीयता कानूनों का एक निश्चित समूह बनाता है, जो कुछ लोगों की कुछ राष्ट्रों की नागरिकता प्राप्त करने की अनुमति देता है, या उन्हें प्रतिबंधित करता हैं।

**ब्रिक्स का क्या अर्थ है?**

विकासशील देशों का एक समूह ब्रिक्स राष्ट्रों का समूह है, जो तीसरे विश्व और विकासशील विश्व के सच्चे नेता हैं। एक तरह से ये देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश हैं। इन राष्ट्रों की ओर से विजेताओं के प्रमाणित पद विश्व संघ के लिए पटल आर्थिक और राजनीतिक कथा को आगे बढ़ाने का प्रयास है, जिनका विश्व व्यापार संगठन, अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष और अन्य पश्चिम प्रभुत्व रखने वाले बहुपक्षीय संस्थान जैसे पश्चिमी विश्व में राष्ट्रों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है। राष्ट्रों के ब्रिक्स समूह का प्रयास ब्रेटन वुड्स (Brethon Woods) संस्थानों के लिए

स्व–वित्तपोषित वैकल्पिक संगठन को बनाए रखना है, ताकि राष्ट्रों के विकासशील समूह की आवाज और वैश्विक सिद्धांत को मजबूत किया जा सके।

## 12.2 ब्राजीलः नागरिकता, शासन और प्रशासन

यदि कोई चयन करता है, तो वह ब्राजील के राष्ट्र–राज्य से आरंभ कर सकता है, क्योंकि यह दक्षिण अमेरिका में सबसे उज्जवल और तेजी से बढ़ते राष्ट्रों में से एक है और अंतराष्ट्रीय संबंधों में गैर–संघर्षपूर्ण इतिहास का प्रतिनिधित्व करता है। यह जस सोली व जस सैंगुनिस (Jus soli and Jus Sanguinis) का सिद्धांत है, जिस पर ब्राजील का राष्ट्रीयता कानून आधारित है। कोई भी व्यक्ति जो स्वाभाविक रूप से ब्राजील राज्य में पैदा हुआ है, वह स्वतः ही ब्राजील राज्य का देशीयकृत नागरिक बन जाता है।

### i) ब्राजील में नागरिकता

ब्राजील के संविधान के अनुच्छेद 12 द्वारा कानून शासित है, जो अधिकारियों को ब्राजील की नागरिकता का पता लगाने के संबंध में नियम बनाने का निर्देश देता है। एक व्यक्ति, जो ब्राजील में पैदा हुआ है, बिना किसी शर्त या अधिक कानूनों को बदले बिना ब्राजील की नागरिकता प्राप्त करता है। लेकिन, इसमें एक अपवाद है जिसके अनुसार, ब्राजील के क्षेत्र में पैदा हुए बच्चे वे हैं, जिनके माता–पिता और भाई–बहन एक अलग राष्ट्रीयता से संबंधित हैं, वे भी ब्राजील के राष्ट्र–राज्य की नागरिकता के

लिए आवेदन कर सकते हैं। यह निःशुल्कता विशेष रूप से ब्राजील में विदेशी राजनयिकों से पैदा हुए बच्चों के लिए लागू होती है।

यह उन लोगों के विषय में था जो विदेशी मूल के हैं, लेकिन उन बच्चों माता–पिता में से एक ब्राजीलियाई है। इसका अनुमान दो तरीकों से लगाया जा सकता है, उनमें से एक यह है कि एक बच्चा, जो ब्राजील के माता–पिता से पैदा हुआ है, जो आगे ब्राजील के वाणिज्य दूतावास के साथ पंजीकृत है, ब्राजीलियाई राष्ट्र–राज्य का नागरिक बनने के लिए स्वतः ही योग्य है और दूसरी शर्त यह है कि ऐसे व्यक्ति को ब्राजील के न्यायाधीश के समक्ष साक्ष्य प्रमाणित करना होगा। वाणिज्यिदूत संबंधी पंजीकरण एक आकर्षक बढ़ते और प्रगतिशील लैटिन अमेरिकी दीर्घकाय मनुष्य के रूप में ब्राजील का नागरिक बनने के लिए एक पूर्ववर्ती कदम के रूप में कार्य करने का सुविधाजनक साधन है।

एक बार लिखित शर्तों को पूरा करने के बाद विदेशी मूल के लोगों को ब्राजील के राष्ट्र–राज्य में नागरिकता प्रदान की जा सकती है। आवेदक को ब्राजील के राष्ट्र–राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए। व्यक्ति को ब्राजील में चार वर्ष की विस्तारित अवधि के लिए निरंतर तरीके से रहना चाहिए। आवेदक को पुर्तगाली की औपनिवेशिक भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। दो अन्य शर्तें लागू होती है जो कहती हैं, कि आवेदक को ब्राजील के राष्ट्र के नागरिक के रूप में रहने के लिए परिवार और

वित्तीय संसाधनों की दक्षता प्रदर्शित करनी चाहिए और अंत में, नागरिक आवेदक की अपराधिकता मौजूद नहीं होनी चाहिए।

वे आवेदक जो ब्राजील में 15 वर्ष की अवधि तक रहे हैं और उन पर आपराधिक अभियोग नहीं है, वे भी ब्राजील के नागरिक बन सकते हैं। इस प्रकार, ऐसे लोग देशीयकृत नागरिक बन सकते हैं, और इन आवेदकों पर अपनी पिछली नागरिकता की स्थिति को छोड़ने का कोई दबाव नहीं होता है।

आमतौर पर, ब्राजील के कानून बहुत सख्त और कठोर नहीं है, क्योंकि वे नए आवेदक को अपनी पिछली नागरिकता त्यागने के लिए नहीं बनाए जाते। इसे वर्ष 2013 में, ब्राजील सरकार ने समाप्त कर दिया और ब्राजील के नागरिक की स्थिति पर सवाल उठाया, जो संयुक्त राज्य का एक साधारण नागरिक था। यह अमेरिकी उच्चतम न्यायालय था जिसने व्यक्ति की नागरिकता को खंडित करने का निर्णय दिया था। दोहरी नागरिकता ब्राजील के राष्ट्रीयता कानून का एक पहलू है, जिसमें जन्म से नागरिकता प्राप्त करना और देशीकरण की ओर ले जाने वाली कानून की उचित प्रक्रिया दोनों को ब्राजील की नागरिकता और अप्रवासन प्रणाली द्वारा अनुमति दी जाती है, जो राष्ट्रपति ट्रम्प के निर्णय के संदर्भ में बड़ी अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के 6 देशों के प्रवेशकों पर प्रतिबंध लगाने के कारण इतना बड़ा मामला बन गया है।

**ii) शासन एवं प्रशासन**

जहां तक ब्राजील के राष्ट्र–राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था का संबंध है, इसमें स्थानीय सरकार की संरचना सहित शासन के शहरी और स्थानीय; दोनों प्रकार के उपकरण शामिल है। ब्राजील की कानूनी प्रणाली रोमन कोड पर आधारित है और राष्ट्र ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार नहीं किया है। प्रशासनिक विभाग एक संघीय जिले के साथ 26 विभागों का गठन करते है। ब्राजील का उपद्रवी प्रशासनिक और शासी इतिहास रहा हैं, जहां देश में वर्ष 1964 में एक सैन्य शासन के रूप में जारी रहा। फर्नाडो कलर डी मेलो, (Fernando Color De Mello) 26 वर्षों की अवधि के बाद से ब्राजील के राष्ट्र–राज्य में प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति बने। इस प्रकार, ब्राजील के राष्ट्र–राज्य के बड़े संदर्भ में एक लोकतांत्रिक लोकाचार और प्रणाली का मार्ग–प्रशस्त करता है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, ब्राजील के राष्ट्र–राज्य में तेजी और हलचल का एक पहलू है। एक बार ब्राजील के राष्ट्र–राज्य में सैन्य शासन के त्याग के तुंरत बाद, लोकतंत्र के विचार को स्थापित किया गया और ब्राजील के सामने उच्च मुद्रास्फीति और भारी विदेशी ऋण का खतरा राष्ट्र के अर्थशास्त्र में आर्थिक सुधारों की शुरुआत के साथ समाप्त हो गया। भारत ने भी तुलना के रूप में 90 के दशक की शुरुआत में लाइसेंस कोटा परमिट राज को समाप्त कर दिया, जिसने भारतीय गणराज्य के विकास और प्रगति को बाधित कर दिया था।

ब्राजील के राष्ट्र–राज्य के संघीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार, कार्यकारी के साथ–साथ संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था ब्राजील के राष्ट्रपति द्वारा चलाई जाती है, जिसे आगे राज्य मंत्रियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। ब्राजील के राष्ट्र–राज्य में

राष्ट्रपति शक्तियों में सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर के रूप में ब्राजील के राष्ट्रपति के कामकाज और व्यवहार और कार्रवाई में विचलन के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने वाले व्यक्ति शामिल हैं। वह ब्राजील के राष्ट्र–राज्य में विधायी शाखा में बजट विधेयक को प्रस्तुत करने और पिछले बजट विधेयकों की प्रस्तुतीकरण के प्रभारी हैं। सक्रिय राष्ट्रपतियों में से एक लूला डा सिल्वा (Lula Da Silva) ने देश में भूख, गरीबी और कुपोषण के खतरे के विरुद्ध बड़े उत्साह से काम किया।

स्थानीय सरकार की संरचना भी ब्राजील के राष्ट्र–राज्य में अच्छी तरह से विकसित है, जोकि संघ, राज्य, शहरों और स्थानीय शासी निकायों द्वारा गठित है, जोकि बड़ी अंतरराष्ट्रीय प्रणाली ने बड़े नगरपालिका और मानक संरचना के समान है। राष्ट्र वर्तमान में 26 राज्यों और एक संघीय इकाई के साथ संपन्न है। महापौर, सचिव, हरा–भरा/विकसित समुदाय ब्राजील के राष्ट्र–राज्य में शासी और प्रशासनिक संरचना का महत्वपूर्ण भाग है। लोकपाल के रूप में जाना जाने वाला एक स्पष्ट रूप से परिभाषित निकाय है, जो ब्राजील के राष्ट्र–राज्य के प्रशासनिक ढांचे में खराब प्रशासन और कमियों के मामलों में शिकायतें दर्ज करके लोगों की लड़ाई संभालता है। तीसरे क्षेत्र का मुद्दा भी ब्राजील में महत्वपूर्ण रूप से रखा गया है। संग्रह में राजनीतिक मंच, मीडिया और अकादमिक शामिल हैं, जो एक छलनी के रूप में काम करते हैं, जिसके माध्यम से लोकप्रिय असंतोष और शिकायतें सुनी जा सकती हैं, और प्रणाली को विकसित करने का प्रयास कर सकती हैं क्योंकि ब्राजील के राष्ट्र–राज्य के सकल घरेलू उत्पादन के महत्वपूर्ण भाग और समूह के लिए गैर लाभकारी वर्णित क्षेत्र है।

## 12.3 रूसः नागरिकता, शासन और प्रशासन

सोवियत संघ रूस का प्रथम परिभाषिक शब्द था (Gorbachev, Yelstin and now Vladimir Putin) क्योंकि सोवियत संघ के विघटन के बाद नए रूस का उदय हुआ। गोर्बाचेव, येल्स्टिन और अब व्लादिमीर पुतिन, जैसे रूसी नेताओं द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों के आगमन तक रूसी राज्य शासन का एक साम्यवादी और तानाशाही प्रारूप था। 21वीं सदी में रूस एक राष्ट्रवादी लोकतंत्र का घर है, जहां साम्यवाद के पदचिह्न अभी भी बने हुए हैं, लेकिन अब यह विकास और प्रगति का उद्योग आधारित और पूंजीवादी उन्मुख प्रारूप है, जो रूस के राष्ट्र–राज्य में नागरिकता और प्रशासनिक व्यवस्था को निर्धारित करता है।

### i) नागरिकता और रूस

रूस अपने नागरिकों के अधिकारों और उनकी सुविधा के कारकों के महत्व को भी महत्व देता है। कुछ शर्तें है, जो साथ–साथ आगे बढ़ती है यदि कोई महान शक्ति की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है जो रूस है। आवेदक को रूसी भाषा बोलनी चाहिए, और उसके पास आय का कानूनी स्रोत होना चाहिए और वह एक वास्तविक और वफादार करदाता होना चाहिए। आवेदक को पिछली नागरिकता की शर्त को रद्द करने के लिए आवेदन करना होगा, यदि कोई हो। आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल न रहा हो और कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिए रूस के राष्ट्र–राज्य में स्थायी निवासी के रूप में रूस में रहता हो।

रूस में नागरिकता का प्रश्न रूसी घरेलू कानून के आधार पर वर्ष 1993 में प्रचारित रूसी संघ के संविधान के मानदंडों के आधार पर तय किया जाता है। रूस के नागरिकों को रूसी भाषा में *ऐसियाने* के रूप में नामित किया गया है, और संजातीय रूसी को *रस्की* कहा जाता है। रूसी साम्राज्य के समाप्त होने के बाद, जाखादी रूस के निधन और विनाश के बाद सोवियत संघ के आगमन से लोगों और नागरिकों के लिए उपयोग की जाने वाली शब्दावली ''सोवियत लोग'' थी।

1999 के स्वदेशवासी अधिनियम के अनुसार, और राज्य अधिनियम के अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि रूस के वे सभी पिछले नागरिक, जिन्होंने अन्य राष्ट्रों की नागरिकता नहीं ली थी, उन्हें रूस के राष्ट्र–राज्य के नागरिक बनने के लिए माना जा सकता है। जस सैंगुनिस (Jus Sanguinis) का कानूनी सिद्धांत रूस के राष्ट्र–राज्य में नागरिकता के मानदंडों को निर्देशित करता है। एक बच्चे को कई अन्य संदर्भों में रूस के राष्ट्र–राज्य का नागरिक भी माना जा सकता है। नागरिक और माता–पिता मूल रूप से रूसी हो सकते हैं या नहीं, यह इतना महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है, जबकि रूसी क्षेत्र में बच्चे का जन्म नागरिकता प्रदान करने की केंद्रीय शर्त होनी चाहिए। यदि बच्चा रूसी क्षेत्र में परिव्यक्त माना जाता है माता–पिता का 6 महीने से अधिक समय तक बच्चे का पता नहीं लगाया जा सका, तो ऐसी स्थिति में भी बच्चा रूस के राष्ट्र–राज्य का नागरिक बना रहता है।

### ii) रूस में शासन एवं प्रशासन

रूसी प्रशासनिक प्रणाली यूरोपीय और पश्चिमी गठन में सबसे पुरानी प्रणालियों में से एक है। रूसी प्रणाली इस अर्थ में सबसे त्रुटिपूर्ण प्रणाली बनी हुई है कि यह अब दुनिया के राष्ट्र का भाग है, लेकिन मास्को के राज्य की राजधानी में सत्ता के महान केंद्रीकरण के साथ रूसी प्रशासनिक व्यवस्था में निरंकुशता के पद्चिह्न अभी भी अंतर्निहित हैं। रूस का संविधान राष्ट्रीय राष्ट्रपति के लिए मजबूत शक्तियों की मांग करता है। रूसी राष्ट्रपति पद अपनी पहुंच और प्रभाव में इतना मजबूत और शक्तिशाली है कि इसे चार्ल्स डी गॉल (Charles De Gsulle) के शासन के तहत 1954 के बाद के युग में फ्रांस के चौथे गणराज्य के समान माना जाता है। ऐसा कानूनी ढांचा है जो समकालीन संदर्भ में रूसी राष्ट्रपति की शक्तियों के स्वरूप और सीमा को निर्धारित करता है (http://www.rogerdarling ton. me. uk/ russioan political system. html)। कभी–कभी यह विचार होता है कि शासन के प्रांतीय ढांचे सहित लगभग 75,000 कर्मचारी भी रूसी राष्ट्रपति की शक्ति और विशेषाधाकिार का हिस्सा हैं। इस प्रकार, रूसी राष्ट्रपति की प्रमुख शक्तियों में से एक रूसी सरकार की कार्यकारी शाखा में महत्वपूर्ण पदों पर महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ करना है।

रूसी राज्य के राष्ट्रपति ड्यूमा के अनुमोदन से प्रधान मंत्री को नियुक्त करते हैं, जो केंद्रीय विधायिका और एक प्रतिनिधि और नामित निकाय है। प्रधानमंत्री रूसी राष्ट्रपति की मृत्यु या मृत्यु के मामले में राष्ट्रपति बनने का अधिकारी है। निम्न सदन राज्य ड्यूमा है और संघ परिषद द्वारा विकसित सभी बिलों को ड्यूमा द्वारा पारित करने की आवश्यकता है। ड्यूमा का गठन प्रतिनिधि द्वारा किया जाता है जिसमें 450 सदस्य होते

हैं। राज्य सदन ड्यूमा के अधिकांश सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा कम से कम 7 प्रतिशत वोटों के साथ सदन या ड्यूमा में एक सीट पर पहुंचने के लिए चुने जाते हैं। वर्तमान समय में, ड्यूमा को एक दिन में पांच वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है।

यद्यपि रूसी लोकतंत्र का विचार एक विचार के स्तर पर प्रयास के रूप में अधिक हो सकता है, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जैसे नेताओं के राष्ट्र पर शासन करने के साथ, लोकतंत्र के रूस के राष्ट्र–राज्य में पूर्ण फलने और विकास के लिए आने में बहुत समय लगता है। रूसी राजनीतिक संगठन जो प्रमुख शक्तियों का उत्पादन करता है उसे सिलोविकी कहा जाता है, जो रूसी परंपरा में सैन्य और सुरक्षा समूह का भाग हैं और अब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के नेतृत्व में हैं। अन्य राजनीतिक संगठन ''एकीकृत रूस'' का होता है, जिसका नेतृत्व दिमित्री मेदवेदेव (Dmitry Medvedev) कर रहे हैं।

रूसी सरकार एक अर्ध–राष्ट्रपति और संघीय राष्ट्र है। ऐसी संरचना के तहत, राष्ट्रपति राज्य के संदर्भ में शक्तियां रखता है जबकि प्रधान मंत्री रूस में प्रशासन के संदर्भ में सरकार को एक साथ रखता है। रूस में संपूर्ण कार्यपालिका रूसी राष्ट्रपति के निर्देशों के तहत चलती है। कार्यकारी–शाखा का महत्वपूर्ण कार्य कानूनों का प्रशासन करना है, क्योंकि वे राष्ट्रपति और राज्य ड्यूमा द्वारा पारित किया जाते हैं। शासन के अन्य स्तंभ का केंद्रीय कार्य न्यायपालिका का होता है, जिसका केंद्रीय उद्देश्य रूसी देश में मानदंडों और कानूनों को बनाए रखना है। रूसी अदालतें दीवानी और आपराधिक

मामलों की देखरेख करती हैं, जबकि मध्यस्थता अदालतें संपत्ति के मुद्दों और वाणिज्यिक विवादों से जुड़ी होती हैं। एक बार फिर राष्ट्रपति न्यायाधीशों की भर्ती करता है, और इस प्रकार रूस में प्रशासनिक तंत्र में झुकाव ऐसा होता है, जो स्वरूप और कार्य में अर्ध–राष्ट्रपति है।

## 12.4 भारतः नागरिकता, शासन और प्रशासन

भारतीय राष्ट्र–राज्य में नागरिकता को पवित्र माना जाता हैं। एक व्यक्ति, जो भारत में पैदा हुआ है, एक ऐसे व्यक्ति के साथ–साथ देश का नागरिक माना जाता है, जिसे भारत का नागरिक होने के लिए स्वाभावित बनाया जा सकता है। भारतीय संघ और एल एम सिंघवी समिति की रिपोर्ट भी भारतीय राष्ट्र–राज्य में दोहरी नागरिकता प्रतिमान को वैध बनाती है। भारत में भी देश में प्रशासनिक और शासी तंत्र के विचार और चतुर कामकाज के साथ–साथ नागरिकता की घटना की अपनी विशिष्ट समझ है नागरिकता मूल रूप से एक विचार है, जो एतिहासिक काल से भारत में लोकतंत्रों के लिचछवी ढांचे से निकला है। भारत में एक राष्ट्रीयता कानून है, जो विकास और प्रगति के लिए आवश्यक मान्यता की गारंटी देता है ताकि भारत में व्यवस्था और प्रशासनिक स्थापन के माध्यम से भारतीयों की पहचान को सुगम बनाया जा सके। फिर भी यदि बहिष्करण और हाशिए पर जाने का खतरा नागरिकता और संबंधित राष्ट्रीय और व्यक्तिगत मान्यता के बड़े विचार पर अपना प्रभाव डालता है, तो व्यवस्थित स्थितियां जनसंख्या की पहचान और विकासात्मक पहलुओं को बाधित कर सकती है।

## i) भारत में नागरिकता

मान्यता के दृष्टिकोण और नागरिकता के विचार की धारणा के अतिरिक्त, वह व्यक्ति जिसे नागरिक माना जाता हैं, वह राष्ट्रीय समाज का हिस्सा बन जाता है, और उस राष्ट्रीय और संवैधानिक स्थिति से अपना आधार प्राप्त कर सकता है। फिर भी जैसे–जैसे राष्ट्र आगे बढ़ता है, हमें राष्ट्र को कानून की किताब के विचार तक सीमित करने की आवश्यकता नहीं है। इसकी अपेक्षा, नागरिकता का विचार यह भी निर्धारित करता है कि व्यक्ति राज्य के साथ कैसे सहभागिता कर सकता है, और भारतीय कानून और संविधान की सीमा में स्वयं को कैसे व्यक्त कर सकता है। नागरिकता का विचार ई प्लुरिबस यूनम के अमेरिकी आदर्श से भी जुड़ा है, जो इस विचार को दर्शाता है कि अनेक में से एक का निर्माण होता है। इस प्रकार, भारत में अनुमत राजनीतिक भागीदारी का स्तर भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, स्वाधीनता और संवैधानिक उदारता की बड़ी मात्रा को दर्शाता है, जिसका भारतीय नागरिक आनंद लेते है और इसके अधिकारी भी हैं। वोट का अधिकार और अन्य मौलिक अधिकार इस बात की अभिव्यक्ति है कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वतंत्रता किस हद तक निहित है।

नागरिकता के मामले में भारतीय राष्ट्रीयता कानून भी बहुत स्पष्ट है। अनुच्छेद 5 से 11 भारतीय संदर्भ में व्यक्ति को नागरिकता के अधिकार प्रदान करते हैं। पहले भारतीयों ने नागरिकता के पश्चिमी का विचार पालन नहीं किया था, लेकिन 26 जनवरी, 1950 को संविधान के पारित होने के साथ, भारतीय अब ब्रिटिश विषय नहीं थे, बल्कि भारतीय

नागरिक थे और भूतपूर्व ब्रिटिश साम्राज्य के भाग के रूप में एक प्रतीकात्मक अर्थ में राष्ट्रमंडल नागरिक भी थे। यह कहा जा सकता है कि 26 जनवरी, 1949 तक राष्ट्र में रहने वाले व्यक्ति स्वतः ही भारतीय राष्ट्र–राज्य के नागरिक माने जाते थे। गोवा, दमन, दीव और नागर हवेली जैसे स्थानों को भी भारतीय राज्य द्वारा प्राप्त किया गया, जिसने भारतीय क्षेत्र की नागरिकता की सीमा को बढ़ाया। कोई यह तर्क दे सकता है कि 26 जनवरी, 1950 के दिन और 1986 के अधिनियम के लागू होने के बीच पैदा हुए किसी भी बच्चे को देश का नागरिक कहा जा सकता है। इस प्रकार, राष्ट्रीयता कानून बहुत स्पष्ट है कि देश का स्वाभाविक नागरिक कौन है और देशीकरण की एक प्रक्रिया मौजूद है, जो देश के नागरिकों के रूप में अधिक व्यक्तियों को शामिल कर सकती है।

### ii) भारत में प्रशासनिक व्यवस्था

सही अर्थों में भारत एक संवैधानिक संसदीय लोकतंत्र है। शासन प्रणाली कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के आदेश के तीन अंगों द्वारा चिहिन्त है। भारतीय प्रणाली एक संघीय संरचना है, जिसमें एकाकी पूर्वाग्रह की स्पष्ट विशेषताएं हैं। देश का संवैधानिक प्रमुख उस देश का राष्ट्रपति होता है, जिसे निर्वाचित प्रधान मंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद द्वारा उचित सहायता और सलाह दी जाती है। कानूनों को संसद में विधान के रूप में लागू किया जाता है, और विधायिका का निर्माण होता है, जबकि न्यायपालिका, जो कि देश के कानून को बनाए रखने वाले न्यायालय है और संविधान सरकार के शेष दो अंगों से स्वतंत्र रहता हैं। सहभागी लोकतंत्र का विचार भी भारतीय

राष्ट्र–राज्य में प्रशासन और शासन के संपूर्ण संदर्भ का अभिन्न अंग और समूह है, जहां संविधान में 73वें और 74वें संशोधनों ने स्थानीय और ग्रामीण प्रशासनों का निर्माण किया है, जो भारत में जमीनी स्तर पर शासन के उत्पति स्थान (मैट्रिक्स) को देखते हैं।

भारतीय प्रशासनिक प्रणाली ऐतिहासिक और व्यवस्थित रूप से कैसे विकसित हुई, इसके बारे में पता होना चाहिए। भारतीय प्रशासन की परंपरा का पता मौर्य साम्राज्य के विचार से लगाया जा सकता है जिसे प्राचीन चरण के रूप में जाना जाता है। मध्य कालीन चरण में मुगल प्रशासन का चरण शामिल है, जबकि ब्रिटिश प्रशासन में भारतीय प्रशासन का अंतिम भाग और अवधि शामिल है। अर्थशास्त्र नामक कौटिल्य ग्रंथ को भारतीय प्रशासन की धारणा और कार्य की उत्पत्ति के रूप में देखा जा सकता हैं। इस कार्य की सुंदरता इस तथ्य में निहित है कि यह कार्य प्रशासन के लिए एक नियमावली मार्गदर्शक है, न कि भारत में प्रशासन के युक्तिकरण का केवल दार्शनिक और सैद्धांतिक प्रयास है। कार्य युद्ध और शांति और निगरानी की व्यावहारिक समस्याओं से संबंधित है, जो प्रकृति और सामग्री में अधिक व्यावहारिक और उपयोगिता–उन्मुख है।

भारत में प्रशासनिक व्यवस्था का मुख्य कार्य यह है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर मौलिक अधिकारों और अनुभागों के उल्लेख और पालन के साथ–साथ भारतीय संविधान का पालन किया जाना चाहिए। प्रतिमान के मुख्य विचारों में से एक

यह है कि शासी संरचनाएं नागरिकों के बीच स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को सुधारने के लिए ईमानदार प्रयास करेगी और इसमें विशिष्ट वर्ग शामिल होंगे। प्रशासन प्राप्ति का वाहन है और समय–समय पर उसका रूप और स्वरूप बदलता रहता है। भारतीय प्रशासन एक जवाबदेह, जिम्मेदार और पारदर्शी है, जहां योजनाओं और सरकारी कार्यों के सुचारू संचालन में बाधा डालने वाली बुराईयों को मुख्य आकर्षण में लाया जाता है। सुधार के हिस्से के रूप में, विभिन्न प्रशासनिक सुधार आयोगों को पारित किया गया है, जो राष्ट्र को पक्षपात, भ्रष्टाचार और जवाबदेही की कमी की समस्याओं से उपर उठाते है, जिन्होंने कुछ सीमा तक राष्ट्र की प्रगति को बाधित किया है। व्यवस्था की एक ठोस आलोचना यह होती है कि ब्रिटिश काल की सामंती मानसिकता अभी भी राष्ट्रीय व्यवस्था में व्याप्त है और प्रशासनिक व्यवस्था को नष्ट करती है।

**बोध प्रश्न 1**

**टिप्पणी** : (i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

(ii) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर मिलाइए।

1) ब्राजील में नागरिकता की विवेचना कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

2) रूस के राष्ट्र–राज्य में नागरिकता के मानदंड क्या है?

.....

.....

.....

.....

.....

3) नागरिकता अधिनियम पर प्रकाश डालिए, जो भारत में नागरिकों के लिए प्रासंगिक हैं।

.....

.....

.....

.....

.....

## 12.5 चीनः नागरिकता, शासन और प्रशासन

चीनी जनवादी गणराज्य (People's Republic of China-PRC) एक ऐसा राष्ट्र है, जो मानक साम्यवादी रूप पर बनाया और स्थापित किया गया है। अब 21वीं सदी के आगमन के साथ, पी आर सी को नई आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जो चीनी राष्ट्र को पूंजीवादी रूप की ओर ले गए हैं। इस प्रकार 21वीं सदी के पश्चात् के विश्व में, चीनी शासन और प्रशासनिक तंत्र गुप्त साम्यवादी रूप से नीचे चला गया है जो हमेशा की तरह अधिक पूंजीवादी और शोषक है। चीनी ने कार्यकारी वर्ग के संदर्भ में, सरकार के प्रबंधकों अर्थात मंदारिन (Mandarins) (चीनी सरकार के दिवान होते थे) के माध्यम से यात्रा आरंभ की है। यह 1890 के पश्चात से है कि चीनी जनवादी गणराज्य में नागरिकों और नागरिकता की व्यवस्था शुरू हुई। प्रणाली की उत्पति विभिन्न चीनी परंपराओं और संस्कृतियों से हुई है, जो माओवादी साम्यवाद के पतन के साथ–साथ अंतरराष्ट्रीय प्रभावों के आगमन और चीन के जनवादी गणराज्य की घरेलू राजनीति में बाजार उन्मुख आर्थिक सुधारों के साथ बदल गई।

### i) चीन में नागरिकता

सभी ब्रिक्स देशों में राष्ट्रीयता कानून सुपरिभाषित हैं। इसी तरह चीन में एक सुपरिभाषित राष्ट्रीयता कानून है। एक व्यक्ति चीन में पैदा होने के उपनियम के साथ चीन का नागरिक बन सकता है या जब दो माता–पिता में से एक चीनी नागरिक हो या नागरिकता देशीकरण की उचित प्रक्रिया के साथ प्राप्त की जा सकती है।

वास्तव में, मुख्य भूमि चीन का निवासी मकाऊ और हांगकांग में चीनी निवासियों के साथ चीन का नागरिक है और क्षेत्र में निवास के अधिकारों का आनंद लेता है। एक तरह से, मुख्य भूमि चीन, हांगकांग और मकाऊ के तीन क्षेत्रों के सभी निवासी भी चीनी नागरिकता के सिद्धांत और व्यवहार का एक हिस्सा और समूह है। नागरिकता मानदंड का अलग रूप उन बच्चों पर लागू होता है, जो हांगकांग और मकाऊ के क्षेत्रों में पैदा हुए है। चीनी राष्ट्रीयता कानून के अनुसार, मुख्य भूमि चीन द्वारा नियंत्रित क्षेत्रों में पैदा हुए बच्चे स्वतः ही चीनी जनवादी गणराज्य नागरिक बन जाते हैं।

यह पी आर सी के बाहर तैनात चीनी नागरिकों का जन्म होता है, तो भी व्यक्ति चीनी नागरिकता प्राप्त करता है। व्यावहारिक रूप से, चीनी क्षेत्र में रहने वाले विदेशी स्थायी नागरिक के रूप में बने रहते हैं और पूर्ण नागरिक नहीं होते है, लेकिन देशीकरण की प्रक्रिया क्रमिक और बहुत धीमी होती है, इसलिए हांगकांग और मकाऊ को क्षेत्रों से भी सभी नागरिकों का देशीकरण नहीं हुआ है। बड़े पैमाने पर देशीकरण का एक उदाहरण तिब्बत से हुआ जब 200 दमन (200 Damans) जो नेपाली मूल के लोग हैं, चीन के जनवादी गणराज्य के स्वाभाविक नागरिक बन गए। इस प्रकार, अन्य ब्रिक्स राष्ट्रों के समान, नागरिकों और नागरिकता के विचार को राष्ट्रीयता कानून की स्थायी स्थिरता के साथ अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है, जो राष्ट्र–राज्यों के ब्रिक्स समूह के बीच एक और समानता है। चीनी राष्ट्र और उसके अधिग्रहित क्षेत्रों जैसे कि हांगकांग और मकाऊ में प्रचलित कानून चीन में बसने वालों और अन्य लोगों को अपनी नागरिकता

घोषित करने की अनुमति देते हैं, यदि वे पहले से ही एक देश या किसी अन्य के प्रति अपनी निष्ठा रखते है।

फिर भी, चीन के नागरिकों की भूमिका बहुत दबी हुए है या कम है, क्योंकि उन्हें अभिव्यक्ति की पूर्ण–स्वतंत्रता का आनंद नहीं मिलता है और चीनी कानून द्वारा असहमति का अधिकार और वैकल्पिक विचार रखने की अनुमति नहीं हैं। साम्यवादी जून्टा लोगों को एक तरह की निगरानी में लोगों की निगरानी और इसके साथ गुलाम की तरह बांधे रखती है। इस प्रकार, चीन को बार–बार मानवाधिकारों के आधार पर चीनी असंतुष्टों और विद्रोहियों का आश्रय देने और संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों में शरण देने के आधार पर बहुत आलोचना का सामना करना पड़ा है।

**ii) चीनः प्रशासनिक व्यवस्था**

चूंकि चीनी जनवादी गणराज्य ब्लॉग जनसंख्या (Blog Population) वाला एक विशाल देश है, प्राचीलकाल से चीन को अनेक प्रशासनिक प्रभागों में विभाजित किया गया है। संवैधानिक रूप से चीन में शासन और प्रशासन के तीन स्तर होने चाहिए, लेकिन व्यावहारिक रूप से, चीनी जनवादी गणराज्य में प्रशासन और शासन के पांच स्तर मौजूद है। चीनी जनवादी गणराज्य में प्रशासन के इन स्तरों में शामिल हैं : प्रांतीय, प्रान्त, जिला, बस्ती और गांव। वर्षों से दो महत्वपूर्ण विभाजन हुए है। पहला चीन के उत्तर पूर्वी हिस्सों में प्रांतीय केंद्रों का पुनर्गठन और दूसरा विकास चीन में स्वायत्त क्षेत्रों की स्थापना है, जिसमें कई स्थानीय संस्कृतियां क्षेत्रों, प्रान्तों, इलाकों और चीन के अन्य

हिस्सों में पहचान के मामले उत्पन्न करती हैं। चीनी राष्ट्र–राज्य में प्रशासनिक प्रकृति और शासन की प्रकृति में विविधता की मांग की जाती है।

एकीकृत शासन के चीनी हमले के पीछे एकता और सामूहिक एकता की एक प्रकार से इच्छा निहित है। किन राजवंश के समय में, संपूर्ण देश को अन्य कुलीन और जनजातियों के साथ छोटे राजाओं, कुलीन (लोगों) और प्रान्त प्रमुखों की अस्थायी वफादारी में विभाजित किया गया था। कई दशकों बाद, चीनी इच्छा जागृत हुई कि चीनी राष्ट्र को झगड़े और विघटन की कुंडली में नीचे नहीं उतरने दिया जाए। इस प्रकार, यह केंद्रीकृत तरीके से शासन और लोक प्रशासन की प्रक्रिया के विकास की ओर ले जाता है। वर्ष 1928 में, केवल जिला और प्रांतों ने प्रशासनिक इकाइयों की संरचना का गठन किया। फिर भी, हजारों किलोमीटर की भूमि और शासन करने के लिए विशाल जनसंख्या के साथ, देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए जिला और प्रान्तों के बीच झूठ बोलने वाले प्रान्तों पर विचार किया गया, और उसके भीतर प्रविष्ट कर कार्य किए गए।

गुजरते समय और शर्तों के साथ, चीनी प्रशासनिक व्यवस्था में कई सुधारों की परिकल्पना की गई है। उन क्षेत्रों के शासन और प्रशासन को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने के लिए कुछ प्रांतों के आकार को कम कर दिया गया है। प्रशासनिक सुधारों का एक अन्य सुधारात्मक उद्देश्य यह है कि प्रशासन के स्तरों को पांच से तीन की संख्या तक हटाने की आवश्यकता है। सरकार और प्रशासन को सरल बनाने के ये उपाय, जो

भाई–भतीजावाद के कमी लाते हैं, और सरकारी कर्मचारियों की संख्या जो इन परिवर्तनों की बजटीय आवश्यकताओं और चीन में प्रशासनिक ढांचे में धोखेबाजी करने के परिणामों में और कमी आएगी। डालियान, निबंगो, किंगदाओं, शेनजेन और जियोमेन जैसे पाँच शहरों के कुछ मामले हैं, जिन्होंने विशेष दर्जा प्राप्त किया है, क्योंकि वे और उनकी अर्थव्यवस्थाएं प्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार से जुड़ी हुई है, और आर्थिक नियोजन और प्रांतों के कार्य शासन से व्यापक रूप से मुक्त है।

## 12.6 दखिण अफ्रीकाः नागरिकता, शासन और प्रशासन

दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप में भिन्न रूप से आगे की ओर अग्रसर देशों में से एक है। सबसे पहले यह ब्रिटिश शासन का घर था, तो ब्रिटिश बसने वालों के साथ स्थानीयकृत था। फिर भी, दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्र–राज्य सभी स्तरों पर नस्लीय भेदभाव की व्यवस्था के लिए जाना जाता है, जिसे आगे रंगभेद के रूप में जाना जाता था। राष्ट्र के प्रशासनिक ढांचे में निहित भेदभाव की प्रकृति के बावजूद बड़ा प्रशासन दक्षिण अफ्रीका में शहरी क्षेत्रों में विकास के स्थानीय और मुख्य नगर मॉडल का एक विवेकपूर्ण मिश्रण है।

### i) दक्षिण अफ्रीका में नागरिकता

दक्षिण अफ्रीका एक प्रमुख ब्रिक्स राष्ट्र है, जो समूह के अंदर नवीनतम समावेश है, जो पूर्ण रूप से पश्चिमी–विरोधी सांचे में कामयाब नहीं होता है। दक्षिण अफ्रीका में नागरिकता के लिए कुछ शर्तें हैं। देश के क्षेत्र में 6 अक्टूबर, 1995 से पहले पैदा हुआ

प्रत्येक बच्चा जन्म के कारक से नागरिक है। साथ ही दतक माता–पिता के दक्षिण अफ्रीका में पैदा हुए व्यक्ति, जिनमें से एक माता–पिता दक्षिण अफ्रीका का नागरिक है, भी राष्ट्र का नागरिक है। दक्षिण अफ्रीका के बाहर जन्म लेने वाले बच्चे, लेकिन उनके माता–पिता में से एक दक्षिण अफ्रीकी सरकार की सेवा में थे या अंतरराष्ट्रीय संगठन से जुड़े थे, जिससे दक्षिण अफ्रीकी सरकार जुड़ी हुई है, वे भी दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्र–राज्य के वास्तविक नागरिक हैं। नागरिकता में देशीकरण भी दक्षिण अफ्रीका में एक स्वीकृत और वैध प्रथा है।

### ii) प्रशासनिक व्यवस्था

दक्षिण अफ्रीका में एक सार्वजनिक सेवा है, जो वर्षों से विकसित हुई है और बदलती भूमिका की अपेक्षा राष्ट्र और शासितों द्वारा की जा रही है। दक्षिण अफ्रीका मे लोक प्रशासन की संपूर्ण सीमा 1994 में लोक सेवा अधिनियम के अंतर्गत आती है। यह अधिनियम सार्वजनिक सेवा के कार्यों को स्थापित करता है और श्रम संबंधों, सेवा की शर्तों और विभिन्न कर्मचारियों के लिए रोजगार के अन्य पहलू को तय करने के साथ–साथ संगठनात्मक संरचनाओं और विभिन्न सरकारी विभागों की स्थापना को देखता है। यह अधिनियम दक्षिण अफ्रीका के प्रशासनिक ढांचे में ई–गवर्नेंस और नैतिकता, अखंडता और भ्रष्टाचार–विरोधी जांच और संतुलन के मुद्दे को भी शामिल करता है, जिसमें वे शर्तें शामिल हैं, जो देश की प्रशासनिक प्रणाली में ध्यानाकर्षक

(एक व्यक्ति जो अनौपचारिक गतिविधियों में सलंग्न संगठन या व्यक्ति की सूचना देता है) की रक्षा करती हैं।

हालांकि, दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, फिर भी नस्लीय भेदभाव के निशान शासन के विचार और कार्य–प्रणाली पर प्रभाव छोड़ते हैं। यह सूचित किया जा सकता है कि लगभग 95 प्रतिशत सार्वजनिक सेवा गोरों के पास है, और केवल 0.6 प्रतिशत लोक सेवा अधिकारी अश्वेत अफ्रीकी के पास है, जबकि अश्वेत अफ्रीकियों के पास सरकार के मध्य और निचले स्तरों के और दक्षिण अफ्रीका में मातृभूमि की स्थापना में भी बहुमत प्राप्त है। यह सब दक्षिण अफ्रीकी प्रशासनिक व्यवस्था में बड़े सुधारों की मांग करता है। यह सुरक्षित रूप से तर्क दिया जाता है कि अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस (ANC) के आने के साथ राष्ट्र में नौकरशाही पर विश्वास नहीं किया जा सकता था और ए एन सी को दक्ष प्रबंधन और कुशल प्रशासन के लिए संरचना को स्थानीय, प्रांतीय और संघीय स्तरों में विभाजित करना पड़ा था।

**बोध प्रश्न 2**

**टिप्पणी** : (i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

(ii) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर मिलाइए।

1) चीन में नागरिकता, शासन और प्रशासन की व्याख्या कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

2) दक्षिण अफ्रीका के प्रशासनिक ढांचे की प्रमुख विशेषताओं की गणना करें।

.....

.....

.....

.....

.....

## 12.7 निष्कर्ष

ब्रिक्स समूह के अन्य राष्ट्रों की तरह, विभिन्न प्रशासनिक संरचनाओं पर दबाव लोक सेवा के प्रशिक्षण, अभिविन्यास और नेतृत्व के महत्व को उजागर करना है, और उद्देश्यों को कार्यक्रमों और परियोजनाओं में परिवर्तित करने और अंतिम गणना में इन कार्यक्रमों और उद्देश्यों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य की क्षमता पर फिर से विचार करना है। इस प्रकार, भ्रष्टाचार, कामकाज में आसानी, गहरी पुरानी जड़े और पारंपरिक प्रणालीगत मुद्दे संस्थानों की क्षमता में सुधार के लिए दीर्घकालिक और

राजनीतिक दृष्टिकोण की मांग करते हैं। प्रशासनिक कामकाज की समावेशी प्रकृति भी उस मुद्दे का महत्वपूर्ण संकेतक है, जहां समानता, बंधुत्व और सामाजिक रूप से न्याय संगत निर्णयों और राष्ट्रों के इन ब्रिक्स समूह की प्रशासनिक संरचनाओं को निर्धारित करने के लिए उपायों की आवश्यकता है।

## 12.8 शब्दावली

**नागरिकता (Citizenship)** : इस शब्द में कुछ मानदंड शामिल हैं, जिन्हें किसी राष्ट्र के नागरिक होने की शर्त के रूप में निर्धारित किया जा सकता है। यह शब्द किसी राष्ट्र की कानूनी स्थिति की ओर संकेत करता है।

**डेनजन (Denizen)** : यह एक विदेशी को अपने दत्तक देश में कुछ अधिकारो की अनुमति देता है। विशेष रूप से कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त जैसाकि नागरिक और विदेशी के बीच अधिकार प्राप्त व्यक्ति।

## 12.9 संदर्भ लेख


Avasthi, A. & Maheshwari S.R. (1982). *Public Administration.* Agra, India: Laxmi Narayan.

Bellamy, R. (2017). *Citizenship: A Very Short Introduction*. Oxford University Press.

Bhattacharya, M. (1987). *Public Administration.* Calcutta, India: World Press.

Elizabeth, W.A. (1989). *Mongolian Rule in China: Local Administration in the Yuan Dynasty*. Harvard University, Asia Center.

Ervin, S. (Ed.). (2017). *Russia: Strategy Policy and Administration*. Palgrave Books.

Government of India. (2008). *Second Administrative Reforms Commission, Tenth Report, Refurbishing of Personnel Administration - Scaling New Heights.* Retrieved from https://darpg.gov.in/sites/default/files/personnel_administration10.pdf

Government of India. (2016). *Annual Report 2015-16.* New Delhi, India: Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions.

Love, J. & Baer, W. (2009). *Brazil under Lula, Economy, Politics and Society Under the Worker President*. Palgrave Macmillan.

Morse, H.B. (2012). *The Trade and Administration of China*. Ulan Press.

Sampson, C. (1983). *Values, Bureaucracy and Public Policy.* London: University Press of America.

Sarkar, S. (2009). *Public Administration in India*. New Delhi, India: Prentice Hall India.

Small, M. (2006). *Being a Good Citizen: A Book about Citizenship*. Capstone Books.

The Citizenship Amendment Act, 2019 NO. 47 of 2019. Retrieved from *https://egazette.nic.in>WasteReadData/2019/214646.pdf*

Thornhill, C., Lle, L. & Dijk, G. (2014). *Public Administration and Management in South Africa: An Introduction*. OUP Southern Africa.

Tocquivelle, A.D. (1880). *Democracy in America*. New York.

## 12.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

### बोध प्रश्न 1

1) आपके उत्तर में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए :

- यह जस सोली और जस सैंगुनिस का सिद्धांत है, जिस पर ब्राजील का राष्ट्रीयता कानून आधारित है।

- कोई भी व्यक्ति जो स्वाभाविक रूप से ब्राजील राज्य में पैदा हुआ है, वह स्वतः ही ब्राजील राज्य का देशीयकृत नागरिक बन जाता है।
- अधिक विवरण के लिए 12.3 देखिए।

2) आपके उत्तर में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए :

- कुछ शर्तें हैं, जो साथ–साथ अग्रसर होती हैं यदि कोई उस महान शक्ति की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है जो रूस है।
- आवेदक को रूसी भाषा बोलनी चाहिए और उसके पास आय का कानूनी स्रोत होना चाहिए और वह एक वास्तविक और ईमानदार करदाता होना चाहिए। आवेदक को पिछली नागरिकता की शर्त को रद्द करने के लिए आवेदन करना होगा यदि कोई हो।
- आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल न रहा हो और कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिए रूस के राष्ट्र–राज्य में स्थायी निवासी के रूप में रहता हो।

3) आपके उत्तर में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए :

12.4 देखिए।

**बोध प्रश्न 2**

1) भाग 12.5 देखिए।

2) भाग 12.6 देखिए।

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

# इकाई 13 नागरिक समाज की बढ़ती भूमिका*

## इकाई की रूपरेखा


13.1 उद्देश्य

13.2 प्रस्तावना

13.3 ब्राजील में नागरिक समाज की बढ़ती भूमिका

13.4 रूस में नागरिक समाज की बढ़ती भूमिका

13.5 भारत में नागरिक समाज की बढ़ती भूमिका

13.6 चीन में नागरिक समाज की बढ़ती भूमिका

13.7 दक्षिण अफ्रीका में नागरिक समाज की बढ़ती भूमिका

13.8 निष्कर्ष

13.9 शब्दावली

13.10 संदर्भ लेख

13.11 बोध प्रश्नों के उत्तर


## 13.1 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात, आपः

- नागरिक समाज का अर्थ और उसके विस्तार पर चर्चा कर सकेंगे;


* डॉ. विश्वरंजन मोहांती, सहायक प्रोफेसर, श्री गुरूतेग बहादुर खालसा कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

- ब्रिक्स में नागरिक समाज की कार्य स्थितियाँ; तथा
- शासन और विषयगत मुद्दों में नागरिक समाज की भागीदारी पर चर्चा कर सकेंगे।

## 13.2 प्रस्तावना

यह इकाई ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) का गठन करने वाले पांच देशों में नागरिक सहायक भूमिका और प्रभाव की जांच का अध्ययन करती है। इन समूहों ने सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन में अग्रणी भूमिका निभाई है। ब्रिक्स की विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों में नागरिक समाज का महत्वपूर्ण योगदान बहुत ही सराहनीय है। नागरिक समाज के योगदान में दो प्रकार के सत्र रहे हैं। एक भाग सामाजिक आंदोलनों के अध्ययन से संबंधित है, जिसने गरीबों और वंचितों के मुद्दों को लिया है और संस्थानों, कानूनों और प्रक्रियाओं के ढांचे में परिवर्तन के माध्यम से सरकार को उनकी जरूरतों के प्रति ग्रहणशील बना दिया है। दूसरा भाग, नागरिक समाज संगठनों के रूप में जाना जाने लगा है, जिन्होंने स्वयं विशेष भूमिका निभाने का उत्तरदायित्व लिया है, जिसमें सरकारी कार्यक्रमों का निष्पादन शामिल है। सामाजिक आंदोलनों और गैर–सरकारी संगठनों ने राजनीतिक प्रक्रियाओं में लोक सेवाओं के प्रावधान में अपने लिए नया स्थान बनाया हैं। नागरिक समाज संगठन (CSOs) सरकार के प्रदर्शन को बेहतर बनाने और लोकतंत्र के मूल्यों को बढ़ाने में सहायता कर रहे हैं।

## 13.3 ब्राजील में नागरिक समाज की बढ़ती भूमिका

ब्राजील में नागरिक समाज की जड़ों का पता सोलहवीं शताब्दी के आरंभ में लगाया जा सकता हैं, जब पुर्तगाल ने ब्राजील में अपना उपनिवेश स्थापित किया था। सांता कैसास प्रथम नागरिक समाज संगठन (सी एस ओ) था, जो बीमार, विधवाओं, अनाथों और परित्यक्त बच्चों की देखभाल के लिए स्थापित किया गया था।

ब्राजील की अर्थव्यवस्था में उदारीकरण के कारण 70 के दशक के दौरान ब्राजील का नागरिक समाज दिखाई दिया। ब्राजील में सरकारी कामकाज के भीतर परिवर्तन लाने के लिए नागरिक समाज समूहों के कई रूप विकसित हुए और अस्तित्व में आए। आंदोलन निम्नलिखित मापदंडों के कारण आरंभ हुआ :

i) स्थानीय और क्षेत्रीय स्तर पर शहरी गरीबों के लोकप्रिय आंदोलन के संगठन;

ii) एकीकृत स्वास्थ्य प्रणाली के लिए स्वच्छता आंदोलन के संस्थान;

iii) राष्ट्रीय शहरी सुधार के लिए संगठित आंदोलन;

iv) प्रोफेसरों, डॉक्टरों आदि, जैसे पेशेवर संघों का उदय; और

v) ब्राजील के ग्रामीण इलाकों में कई संगठनों का गठन।

1974–1985 के अवधि में लोकतांत्रिक आंदोलनों और विविध प्रकार की सामूहिक कार्रवाईयों का विकास हुआ, जिसके कारण देश के मूल स्वैच्छिक संघों में पर्याप्त

परिवर्तन हुए। ब्राजील के लोकतांत्रिक आंदोलनों ने संघ के स्वैच्छिक और स्वायत्त रूपों का उत्पादन करने की प्रवृत्ति में उल्लेखनीय वृद्धि को आकार दिया।

गरीब अपनी आजीविका के कारण बहुत अधिक वंचित थे और लोक वस्तुओं तक उनकी पहुंच सीमित थी, जो कि सत्तावाद के कारण ब्राजील के शहरों में असमान रूप से वितरित थी। ब्राजील के सभी क्षेत्रों में शैक्षिक सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं और पानी की सुविधाएं स्तर से निम्न थीं। यह ब्राजील में सत्तावाद के स्वरूप के कारण हुआ। नागरिक समाज के ढांचे में गरीबों के जुड़ाव ने एक नई शक्ति स्थापित करने में बहुत ही गतिशील भूमिका निभाई, जो लोक वस्तुओं के आवंटन के विकास में हेरफेर कर सकती थी।

आरंभ में, नागरिक समाज समूहों ने राज्य और राजनीतिक दलों के हस्तक्षेप से अपनी स्वायत्ता की मांग की। 1930 और 1980 के दश्क के दौरान, ब्राजील में नागरिक समाज समूहों के कामकाज पर राज्य के हस्तक्षेप के प्रमाण थे। विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में नागरिक समाज की उभरती भूमिका के कारण स्वायत्तता की प्रभावी रूप से मांग की गई थी। 1977–1985 की अवधि की विशेषता यह थी कि नागरिक समाज समूहों ने भी राज्य के हस्तक्षेप के बिना नीतियों के प्रशासन की गतिविधियों से स्वायत्तता की मांग की थी। इस तरह 80 के दशक में साओ पाउलो (Sao Pualo) में नागरिक समाज संगठनों द्वारा स्वास्थ्य आंदोलन आरंभ किया गया था। इसने राज्य से स्वतंत्र रूप से स्वास्थ्य नीतियों को प्रस्तुत करने का दावा किया। एक अन्य सूचनात्मक शहरी सुधार

आंदोलन भी उसी मंच से कुछ अन्य नागरिक समाज संगठनों द्वारा स्वतंत्र रूप से शुरू किया गया था। 80 के दशक में पोर्टो एलेग्रे में UAMPA ने बजट मुद्दों से संबंधित निर्णय लेने का प्रस्ताव देने का प्रयास किया। यह पड़ोसी संघों की एक परिषद पर आधारित था। लोकतंत्रीकरण के दौरान नागरिक समाज की संप्रभुता नागरिक समाज के अभिनेताओं/कार्यकर्ताओं की अपनी स्थिति की आत्म–समझ का प्रभाव मात्र थी। नागरिक समाज संगठनों की भूमिका को दो मूल विचारों के संदर्भ में स्पष्ट रूप से देखा जाता है :

i) स्वैच्छिक संघों की संख्या में मात्रात्मक वृद्धि और लोक नीतियों में उनके निवेश (इनपुट); और

ii) राज्य से स्वतंत्र रूप से लोक नीतियों को मान्यता देने में नागरिक समाज का योगदान।

ब्राजील का नागरिक समाज स्वायत्तता और राजनीतिक निर्भरता के बीच की स्थिति में उभरा।

इस प्रकार, दो प्रक्रियाओं के आधार पर इसे एक नई भूमिका में देखा जाता है :

i) आधुनिकीकरण की अलोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति लोकप्रिय क्षेत्रों का प्रतिक्रियाशील व्यवहार; और

ii) लोक नीतियों के कार्यान्वयन में राज्य से प्रभावी रूप से जुड़े संघों के समूहों का गठन।

लोकप्रिय क्षेत्रों के व्यवहार ने नागरिक समाज संघों को लोकतांत्रिक गहनता की प्रक्रिया में मजबूत और शक्तिशाली बनाया। नागरिक समाज भी जन कल्याण प्रदान करने में शहरी गरीबों के साथ जुड़ा हुआ है। साओ पाउलो जैसे शहरों में इस संघ का मजबूत अस्तित्व है। यह उन शहरों में भी शक्तिशाली है, जहां कैथोलिक चर्च ने प्रगतिशील नीतियों का पालन किया और सामुदायिक मुद्दों से जुड़े हैं। अन्य समूहों को भी लोक नीतियों की प्राप्ति में राज्य की भागीदारी से जोड़ा जा रहा है। इन संघों का ब्राजील में वामपंथी और कार्यकर्ता दल से भी जुड़ाव है। लोक नीति संघ भी राज्य की कार्रवाई के लोकतंत्रीकरण में पहल कर रहा है।

नागरिक समाज 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बाजार और समाज के बीच सीमांकन से बहुत जुड़ा हुआ है। यह ब्राजील में विकसित लोकतंत्र के समय में विकसित हुआ था। इसने अपने तरीके से त्रिपक्षीय स्पष्टीकरण दिया। नागरिक समाज की भूमिका उस समय बहुत स्पष्ट थी, जब इसे अर्ध–स्वायत्त (Semi Auto---) माना जा रहा था। इसने अपनी संगठनात्मक गतिशीलता को बचाए रखने में राज्य के साथ सहयोग और हस्तक्षेप किया। ब्राजील में नागरिक समाज की बढ़ती भूमिका को 90 के दशक में प्रभावी ढंग से सिद्धांतित किया गया था। इसने स्वायत्तता की सहायता से नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं के निहितार्थ को सिद्ध किया। नागरिक समाज की स्वायत्तता

संगठनात्मक स्वायत्तता के रूप में और दूसरी तरफ राज्य की कार्रवाई के लिए बहुत अधिक निहित थी। स्वायत्तता का भाग सत्तावाद के दौरान प्रभावी ढंग से स्थापित किया गया था, लेकिन दूसरी ओर, यह लोकतांत्रीकरण के अन्तर्गत लंबे समय तक नहीं चल सका। नागरिक समाज का दूसरा ऐतिहासिक विकास 90 के दशक में अस्तित्व में आया। इसने नागरिक समाज और राज्य के बीच पारस्परिक निर्भरता के मुद्दे पर प्रश्न किया।

ब्राजील के समाज में, नागरिक समाज और मजबूत लोकतंत्र के बीच संबंधें को अंतर–निर्भरता की व्यवस्था के सहारे धीरे–धीरे उकसाया गया था। राज्य के साथ अवसर को अलग करने के लिए ब्राजील में नागरिक समाज समूह तेजी से बढ़े, और नीति परिषदों में राज्य के साथ परस्पर संबंद्ध बनाना आरंभ कर दिया। नागरिक समाज समूह विशिष्ट विकास परियोजनाओं में भी सक्रिय हैं, जो लोक नीतियों को मान्यता देने के लिए निष्पादन और प्रक्रिया को पूरा करने में संलग्न हैं। ब्राजील में नागरिक समाज की बढ़ती भूमिका निम्नलिखित कारणों से स्पष्ट थीं :

i) अधिनायकवाद द्वारा विकसित सामाजिक विरोध, जिसने गरीब जनसंख्या को ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर प्रेरित किया; और

ii) न्यूनतम सामाजिक सेवाओं के आश्वासन के बिना ब्राजील के विशाल शहरों के भीतर गरीब जनसंख्या की पुनःव्यवस्था।

शहरों में गरीब लोग अपने अधिकारों और सामाजिक सेवाओं जैसे बिजली, परिवहन और सीवरेज (Sewerage) आदि को प्राप्त करने के आधार पर वंचित थे। शहरों में गरीबों ने अपने अस्तित्व के लिए अपने बुनियादी अधिकारों की मांग की, जिससे ब्राजील में नागरिक समाज संगठनों ने अपनी ओर से उनकी उत्तम सहायता की।

1988 में फिर से लोकतंत्रीकरण के आरंभ के बाद से ब्राजील ने नागरिक समाज संगठनों (सी एस ओ) की भूमिका में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे हैं। तब से ब्राजील के नागरिक समाज ने स्वयं को मजबूत किया चाहे वह सामाजिक आंदोलनों से हो या विशेष गैर–सरकारी संगठनों की सहायता। ब्राजील 2013 के लोक प्रदर्शनों की पृष्ठभूमि में संक्रमण और अनिश्चियता के दौर से गुजरा है। हालांकि, हाल ही में सी एस ओ की भूमिका में गिरावट देखी गई है, क्योंकि इन संगठनों को नीति निर्माताओं द्वारा कम परामर्श दिया जाता है।

सामाजिक आंदोलन, समुदाय आधारित संगठन और तीसरे क्षेत्र के संगठन ब्राजील में तथाकथित नागरिक समाज संगठन हैं। ब्राजील में नागरिक समाज संगठन विशेष रूप से शासन को विकसित करने, पर्यवेक्षण का विस्तार करने और सामाजिक पूंजी बढ़ाने के लिए सत्ता के अपने बाहरी प्रभाव का उपयोग करने पर विचार कर रहे हैं। वर्तमान में तीन परस्पर जुड़ी राजनीतिक प्रक्रियाओं ने ब्राजील में नागरिक समाज को सशक्त बनाने के लिए प्रभावित किया। ये निम्नलिखित विचारों पर आधारित है।

1) 80 के दशक के मध्य में प्रतिनिधि लोकतंत्र का आगमन;

2) संस्थाओं के सहभागी ढांचे की उभरती भूमिका; और

3) नव–विकास–मानसिक राज्य और सामाजिक कल्याण नीतियों का गठन।

ब्राजील में प्रतिनिधि लोकतंत्र ने कई नागरिक समाज संगठनों के प्रत्यक्ष रूप से विवादास्पद राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने की अनुमति दी। लोक–नीति प्रक्रिया के निष्पादन और कार्यान्वयन में संस्थानों के सहभागी ढांचे की भूमिका के सी एस ओ ने अनुमति प्रदान की। ब्राजील सरकार ने 2000–2009 के बीच आर्थिक विस्तार के समय कई नागरिक समाज संगठनों को सामाजिक कल्याण नीतियों के कार्यान्वयन के लिए प्रयास करने को कहा। ब्राजील में नागरिक समाज संगठनों के पास नीति निर्माताओं और आम लोगों को प्रभावित करने के लिए अपने स्वयं के नीतिगत ढांचे और रणनीतिक विकल्प है। ब्राजील के शहरों में बड़ी संख्या में नागरिक समाज के नेता हैं, जो आम आदमी के उद्देश्यों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सक्रिय हैं। नागरिक समाज संगठन प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में संलग्न हैं, लोक अधिकारियों के साथ छोटे से छोटे संपर्क में प्रवेश कर रहे हैं, और नीति बनाने वाली संस्थाओं के साथ जुड़ रहे हैं। नागरिक समाज संगठनों को आधिकारिक तौर पर ब्राजील में राज्य की भूमिका के साथ स्वीकार किया जाता है। उनके पास सामाजिक सेवाएं प्रदान करने के लिए कौशल और विशेषज्ञता है, और सरकारी बंधन को बंद करने के लिए राजनीतिक नेताओं के साथ उनका पारस्परिक संबंध इंटरफेस है। कुछ सी एस ओ विशिष्ट दृष्टिकोण का अनुसरण कर रह हैं, जो ब्राजील में लोकतात्रिक

आंदोलनों के बारे में अंतःदृष्टि प्रदान करते है। नागरिक समाज की रणनीतियों ने राज्य की भूमिका और नागरिक स्वतंत्रता की सुरक्षा, नए लोकतांत्रिक संस्थानों के निर्माण और राज्य अनुबंधों की आउटसोर्सिंग के साथ भी बातचीत की। यह ब्राजील में लोकतंत्र और नागरिक समाज के बीच पर्याप्त प्रतिक्रिया प्रदान करता है। नव–विकासवादी राज्य के उदय के साथ, कई नागरिक समाज संगठनों की भागीदारी का दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने लोक अधिकारियों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने और नए तरीकों से सोचने के लिए अपनी विशेषता, कौशल और तकनीकी प्रतिस्पर्धा का उपयोग करना आरंभ कर दिया। ब्राजील के गरीब समुदायों में नागरिक समाज संगठन अपने प्रेरित हितों का पालन करने के लिए विकल्पों के एक संकीर्ण समूह से बाहर निकल रहे हैं।

कई नागरिक समाज संगठन (सी एस ओ) सामूहिक गतिमान प्रक्रिया के माध्यम से अपनी सामाजिक और लोकतांत्रिक सेवाओं को सक्रिय रूप से बढ़ा रहे हैं। सामूहिक कार्रवाई लोकतांत्रिक वातावरण के मौजूदा परिप्रेक्ष्य में अधिक स्वेच्छा से उपलब्ध है। नए विरोध सामूहिक गतिमान और ब्राजील में गैर–सरकारी संगठनों की सक्रिय भूमिका के लिए सक्रिय समर्थन का सुझाव देते हैं। इसमें उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है और नागरिकों को जुटाने, वृद्धिशील नीति निर्माण को बढ़ाने और सामाजिक और नीति व्यवस्था की ओर बढ़ने में सरकार के प्रदर्शन की प्रभावशीलता में वृद्धि की है। ब्राजील के समाज में प्रभावी संपर्क बनाने के लिए इन सी एस ओ ने अपनी प्राप्त स्थिति और मान्यता भी प्राप्त की है।

ब्राजील में कई नागरिक समाज समूहों ने उच्च स्तरीय कार्यकारी के साथ बैठकें आयोजित की हैं। उन्होंने वार्षिक सम्मेलन के साथ कई विषयगत सम्मेलनों का आयोजन किया है, जिसमें न्यू डेवलपमेंट बैक पर कार्यशालाएं और 2014 में प्रथम महिला ब्रिक्स मंच को शामिल किया हैं। ब्राजील के प्रशासन ने राष्ट्रीय स्तर पर कुछ समूहों के साथ सामान्य बैठकें आयोजित की। ये दायित्व ब्रिक्स के विकास में अपने नागरिकों को जोड़ने, एक से अधिक भागीदारी प्रक्रिया की सहायता से दोनों सरकारों की ओर से अधिक सरलता और जिम्मेदारी से एक परिवर्तन को प्रकट करते हैं। एक नागरिक समाज के लिए योजनाएं गति प्राप्त करने के लिए मार्ग प्रशस्त करती हैं। ब्रिक्स नागरिक समान गोलमेज सम्मेलन के लिए एक नई वेबसाइट अक्टूबर, 2014 में आरम्भ की गई थी। यह ब्रिक्स नागरिकों को 'अभूतपूर्व राजनीतिक पाठ्यक्रम' के रूप में दर्शाता है, जिसे पहली बार 2015 में ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलन के अधिकार क्षेत्र में प्राप्त किया गया। ब्राजील में नागरिक समाज ने स्थायी आर्थिक उन्नति और सामाजिक सम्मेलन को विकसित करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के उपयोग के संबंध में, व्यापार और शिक्षा के साथ–साथ सरकारी सूचना में उसका उल्लेख किया गया। ब्रिक्स नागरिक समाज गोलमेज सम्मेलन (BRICS Civil Round Table) ने 2012 से सुझाव को शंकित किया है, और ब्रिक्स विशेषज्ञ दल परिषद ने ब्रिक्स के लिए दीर्घकालिक विचार का सीमांकन करते हुए एक सर्वव्यापी दस्तावेज का नियोजन किया है। इसमें नागरिक समाज संगठनों के विविध समूह संलग्न है और मान्यता प्राप्त है और समय के साथ, सरकार के प्रदर्शन के साथ विकसित भी हुए है।

अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंडा में बढ़ती शक्तियों के कारण अंतर्राष्ट्रीय विस्तारित सहयोग के क्षेत्रों में ब्रिक्स देशों के नागरिक समाजों की उर्ध्व भूमिका को दर्शाया है। वर्तमान में ब्राजील में नागरिक समाज समूह अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में चल रहे मुद्दों और चुनौतियों का प्रभावी ढंग से उत्तर दे रहे हैं। आर्थिक मंदी, जलवायु और पर्यावरणीय विरोध, प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती घटनाओं के प्रति एकाग्रता ने ब्राजील में नागरिक समाजों को और अधिक अखंड बना दिया है। वे देश में चल रही इन चुनौतियों का लोकतांत्रिक तरीके से मुकाबला कर रहे हैं। नागरिक समाज समूहों ने ब्रिक्स देशों की सहायता से विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विभिन्न विश्वव्यापी बैठकों में भाग लिया। हाल ही में, यह न केवल ब्राजील से था, बल्कि विभिन्न सामाजिक आंदोलनों के प्रतिनिधियों ने भी जनमंचों में भाग लिया। समूहों का उद्देश्य नव–उदारवाद के विरुद्ध आवाज उठाना था। जनता का मंच गोवा में 13–14 अक्टूबर को आयोजित किया गया था। विश्व भर के श्रमिक संघ, अकादमिक, नागरिक समाज समूह और अन्य प्रतिनिधि गोवा में एकत्रित हुए। समूहों ने अपनी प्रबुद्ध दृष्टि साझा की, नोट्स साझा किए और नव–उदारवाद और सामुदायिक वैश्वीकरण के विरोध में सामान्य लक्ष्य बनाने का प्रयास किया। ब्राजील के नागरिक समूह भी नव–उदारवाद, महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण शासन के एजेंडे पर काम कर रहे हैं।

ब्राजील में नागरिक समाज समूह भी उभर रहे हैं और खाद्य और कृषि, निवेश और व्यापार प्राकृतिक संसाधनों के शासन, अर्थव्यवस्था विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नागरिक और मानवाधिकार जैसे विषयगत मुद्दों के क्षेत्र में बहुत गतिशील भूमिका निभा रहे हैं।

## 13.4 रूस में नागरिक समाज की बढ़ती भूमिका

पिछले 25 वर्षों के उल्लेखनीय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन ने रूसी नागरिक समाज को बदल दिया है। रूस में नागरिक समाज व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यों, संगठनों और संस्थानों द्वारा साझा हितों को आगे बढ़ने के लिए बनाया गया है। यह संकेत नागरिक समाज की संस्थागत व्यवस्था और इसके गठन की अस्थिर स्वरूप दोनों को दर्शाता है। रूस में नागरिक समाज समूहों की मूल विशेषताएं निम्नलिखित संकेतकों को दर्शाती हैं :

i) **नागरिक कार्य :** सामाजिक और राजनीतिक संगठनों में व्यक्तिगत विचार–विमर्श की तीव्रता।

ii) **संगठन का चरण** : संस्थागतकरण की सीमा, जो नागरिक समाज के गठन को दर्शाती है।

iii) **मूल्यों का पालन करना :** नागरिक समाज को सकारात्मक मूल्यों को आत्मसात करने और प्रतिबिंबित करने के लिए किस सीमा तक देखा जाता है।

iv) **प्रभाव का अवलोकन :** आंतरिक और बाहरी जागरूकता दोनों के अनुसार नागरिक समाज का स्पष्ट सामाजिक और नीतिगत आघात।

v) **पर्यावरण का बाहरी प्रभाव :** यह सामाजिक–राजनीतिक सांस्कृतिक स्थितियों को संदर्भित करता है। यह नागरिक समाज की गतिविधि की सीमा को संदर्भित करता है।

रूस में नागरिक समाज की बढ़ती भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इसके ऐतिहासिक विकास की चर्चा *चार* चरणों में की जा सकती है :

i) रूस में नागरिक समाज की प्रथम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को संस्थागतकरण के आधार पर चित्रित किया जा सकता है। 1760–1860 की अवधि में विज्ञान, अवकाश, कला और धर्मार्थ कार्यों से जुड़े लोक संगठनों का निर्माण हुआ। इस समय के दौरान रूसी भौगोलिक समाज की स्थापना की गई थी, जो प्रत्यक्ष रूप से रूसी साम्राज्य की भूमि, लोगों और संसाधनों से जुड़ा हुआ था।

ii) नागरिक समाज की द्वितीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमि व्यावसायिकता, लोकतंत्रीकरण और रूसी नागरिक समाज की गतिविधि के विस्तार के विकसित दृष्टिकोण के उद्भव के साथ स्पष्ट थी। रूस में नागरिक समाज का गठन 1861–1917 की अवधि के बीच स्पष्ट था। 1860 के दशक के पुनःगठन ने रूस में दासत्व (serfdom) को समाप्त किया और कानूनी व्यवस्था को बदलने और लोगों को मूल नागरिक अधिकारों की पेशकश करने और स्थानीय शासन के क्षेत्रों में आवंटित शक्तियों को बदलने का प्रयास किया। वैज्ञानिक और शैक्षिक समाज की स्थापना हुई और विशेष रूप से सदस्यों ने 1891–1892 के अकाल में भूखे

किसानों को सहायता प्रदान की। समाज ने आधुनिक सामाजिक आंदोलनों की विशिष्टता को अपनाया जिसे सरकार ने स्वीकार किया। नागरिक समाज संगठनों की बढ़ती गतिविधि प्रत्यक्ष रूप से रूसी समाज के औद्योगीकरण और शहरीकरण के चारों तरफ के विकास में लगी हुई थी। संचार, मीडिया के तेजी से परिवर्तन ने ज्ञान की जानकारी और अन्य उपलब्धियों के आदान–प्रदान को गति दी। औद्योगिक क्रांति के विकास और रेलवे के विकास ने वैज्ञानिक और तकनीकी समाजों के गठन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया। रूस के आम आदमी को मूलभूत सेवाएं प्रदान करने के लिए रूसी तकनीकी समाज का भी गठन किया गया था। 19वीं शताब्दी के अंत में चिकित्सा समितियों, शैक्षिक समाजों और शिक्षक संगठनों के गठन के लिए लोक स्वास्थ्य सेवाएं और राष्ट्रीय शैक्षिक प्रणाली प्रत्यक्ष प्रभावित हुई।

रूस में नागरिक समाज संगठनों ने सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, विज्ञान, सामुदायिक स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं का सामना किया किन्तु राज्य को सेवाएं प्रदान करने का अधिकार नहीं था। ये नागरिक समाज संगठन लंबी अवधि के ऋण देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के माध्यम से प्रत्यक्ष सामाजिक सुरक्षा में लगे हुए थे। रूसी नागरिक समाज समूहों ने रूसी समाज में लोक संगठनों के गठन की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लोक पहल और स्व–संगठन के योगदान को राज्य द्वारा स्वीकार किया गया था। रूसी समाज

में लगभग 4,800 गैर–सरकारी संगठन पंजीकृत थे। 1906–1909 की अवधि चिहिन्त है।

iii) नागरिक समाज के गठन की तृतीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 1917–1980 के दशक की अवधि के दौरान देखी गई। कई नागरिक समाज संगठनों का राष्ट्रीयकरण किया गया। राज्योन्मुखी नागरिक समाज संगठनों की स्थापना राज्यों की आवश्यकता थी। यह समाजवाद का मुख्य अभियान था। रूस में नागरिक समाज की बढ़ती भूमिका के लिए विकासात्मक सहायता प्रदान की गई थी। वे पर्यावरण, मानवाधिकार और शासन जैसे क्षेत्रों में लगे हुए थे। 1920 के दशक की अवधि को नागरिक समाज संगठन (सी एस ओ) के ऐतिहासिक विकास में देखा जा सकता है। संगठन की सामाजिक नींव स्थापित की गई और कई बुद्धिजीवी श्रमिक संघों में शामिल हो गए। अन्य साधारण प्रतिनिधि वैज्ञानिक संगठनों में शामिल हो गए। ये साक्षरता, शिक्षा, पर्यावरण और नागरिक अधिकारों के लिए काम कर रहे थे। सी एस ओ में सामाजिक समस्याओं के लिए कई विकल्पों को प्रस्तुत किया, इस तथ्य के सामने कि राज्य गैर–सरकारी संगठनों की पहल में सहायता करने के लिए सक्षम नहीं था।

कई सी एस ओ (CSO) जैसे ओसोवियाखिम (Osoviakhim) (USSR के रक्षा और विमानन रासायनिक निर्माण के लिए सहायता समितियों का संघ), नास्तिकों का संघ और सोवियत सिनेमा के दोस्तों का समाज प्रभावी शासन के क्षेत्र में

प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे। विकास कार्यों के लिए रूसी समाज में लगभग 11 मिलियन से अधिक नागरिकों को शामिल करने के लिए जन समाज का गठन किया गया। उनका अस्तित्व और गतिविधि समाज द्वारा निभाई गई भूमिका के कारण नाटकीय रूप से बदल गई। राजनीतिक जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रभाव बहुत सराहनीय था। उस समय, 50 नए संघ विकसित हुए, जिनमें बुजुर्गों, डिजाइनरों और बच्चों को शामिल किया गया। विरोधी राजनीतिक आंदोलन उभरा, जिसने रूसी समाज में एक उत्पादक की भूमिका निभाई। शासन की आलोचना करने का प्रयास किया गया और मानवाधिकारों और राजनीतिक संगठनों की स्थापना की गई।

iv) चतुर्थ चरण 1980 के दशक से अब तक देखा गया है। 1980 के दशक के बाद से, कई नागरिक समाज संगठन तेजी से विकसित हुए। 1980 के दशक के अंत में, पारिस्थितिक समाज और पारिवारिक क्लब स्थापित किए गए थे, जिसमें 14 वर्ष से अधिक आयु के 8–10 प्रतिशत शहरी लोग शामिल थे। लोगों के जीवन–स्तर में तेज गिरावट आई, जिसके कारण रूसी समाज में स्वयं सहायता समूह बनाने की आवश्यकता अनुभव हुई। लोक संघों पर सोवियत कानून के कार्यान्वयन, और लोक संघों और धर्मार्थ संघ के कार्यों में संशोधन करने वाले रूसी संघ के कानूनों ने सी एस ओ के गठन को प्रोत्साहित किया। नागरिक समाज संगठनों को मजबूत करने के लिए, कई विदेशी दानकर्ताओं ने संगठनों के सुचारू संचालन के लिए वित्तीय सहायता दी। विदेशी दानदाताओं

ने प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने में नागरिक समाज के अमेरिकी मॉडल के सांस्कृतिक हस्तांतरण में सहायता की।

रूस में नागरिक समाज का मानचित्रण वयस्क रूसियों के 7.8 प्रतिशत के मुख्य समूह का गठन करता है। वे नागरिक पहल और अन्य स्वैच्छिक कार्यों में संलग्न थे। दूसरा समूह अधीन राज्य समूह का गठन करता है। ये समूह हमेशा अन्य संयुक्त कार्यों में लगे रहते थे। 26.5 प्रतिशत इस समूह के है। उपनगर समूह का गठन सामूहिक संग्रहण को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। वे धर्मार्थ गतिविधियों में लगे हुए थे। बाहरी लोगों का गठन 8.8 प्रतिशत है जो प्रतिरोधक समूह से संबंधित है, जिनका वाणिज्यिक संगठनों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है।

रूस में 8.9 प्रतिशत सामाजिक रूप से आधारित नागरिक समाज संगठनों का संघ है। 4.7 प्रतिशत स्वैच्छिक आधारित संगठनों का गठन करते है, और 28.5 प्रतिशत रूस में अन्य संगठनों से संबंधित है।

रूस में नागरिक समाज का मूल्यांकन 146,000 सक्रिय नागरिक समाज संगठनों को शामिल करने के लिए किया जाता है। रूस में नागरिक समाज का विकास कई कारणों से होता है, जिसका आकलन जमीनी स्तर से किया जाता है। इसमें अर्थव्यवस्था, संचार कार्य और शिक्षा स्तर शामिल हैं। नागरिक समाज पर राज्य की नीति कानूनी ढांचे, संचार की मार्गदर्शिका और राज्य संसाधनों के द्वारा वैध दान है। लगभग 15–20 वर्षों के लिए राज्य के नागरिक समाज के व्यवहार में पूर्ण– परिवर्तन का मूल्यांकन

किया गया है। नागरिक समाज की बढ़ती भूमिका को समर्थन देने के लिए रूसी संघ के नागरिक सदन की स्थापना की गई थी। सी एस ओ के लिए राज्य अनुदान प्रदान किया गया था। सी एस ओ की गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए कानून को संशोधित किया गया था। नागरिक समाज संगठनों की सहायता के लिए मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया था। राज्य ने अपना दृष्टिकोण बदला और नागरिक समाज के विकास के लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया प्रदान की। आर्थिक विकास रूस में नागरिक समाज को विकास प्रदान करता है। इनमें क्रमिक विकास, व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट (परोपकारी संसाधन) और स्वैच्छिक योगदान शामिल हैं। सामाजिक क्षेत्र में नागरिक समाज के कार्यों के लिए राज्य नैतिक समर्थन भी उपलब्ध है। नागरिक समाज की बढ़ती भूमिका में रूसी आबादी का शैक्षिक स्तर एक चिंता का विषय है। शिक्षण संस्थानों में सी एस ओ के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है।

## 13.5 भारत में नगरीय समाज की बढ़ती भूमिका

शासन से सरकार की ओर बढ़ने में, भारत में नागरिक समाज की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण रही है। इस स्थान–परिवर्तन में दो प्रकार के प्रभाव सूल (Filament) रहे हैं। एक सामाजिक आंदोलनों का रहा है, जिन्होंने गरीबों और वंचितों की देखभाल की है, और सरकार को स्थापना, कानूनों और कार्यों में परिवर्तन के माध्यम से उनकी आवश्यकताओं के लिए सुलभ बना दिया है। दूसरे की, गैर–सरकारी संगठनों की उभरती हुई भूमिका के रूप में जाना जाने लगा है, जिन्होंने स्वयं मिश्रित जिम्मेदारी ली है, जिसमें सरकारी कार्यक्रमों की प्राप्ति भी शामिल है। सामाजिक आंदोलनों और

गैर–सरकारी संगठनों की नव–उभरती जिम्मेदारी ने राजनीतिक प्रक्रिया और लोक सेवाओं को चलाने में नई छाप छोड़ी है।

संरचित स्वैच्छिक क्रिया/कार्यकारी का भारत में व्यापक वर्णन है। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में, राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों के दौरान की गई बड़े पैमाने पर भर्ती और राजनीतिक अभियान स्वैच्छिक एजेंसियों के विस्तार में प्रमुख मुद्दा थे। उत्पादक क्रियाओं की गतिविधियाँ 1920 के दशक से आरंभ हुई। महात्मा गांधी द्वारा किए गए प्रयास थे, जिसमें आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन हुए थे, जिसने नागरिक समाज संगठनों के विकास को प्रेरित किया। हमारे लोकतांत्रिक संविधान के आरंभ होने के पश्चात् इनमें से कई गांधीवादी संगठनों का नेतृत्व जनता ने किया और इन संघों ने हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों की प्रगति के लिए सरकार के साथ मिलकर दृढ़ता से काम किया। खादी और ग्राम उद्योग, पीपुल्स एक्शन डेवलपमेंट इंडिया (People's Action Development India) और केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड (Central Social Welfare Board) जैसे अन्य संघ भी सामाजिक–आर्थिक परिवर्तनों के लिए कई नागरिक समाज संगठनों को सुधारने और कोष प्रदान करने के लिए 1950–1960 के बीच की अवधि में संलग्न थे। 1960 के दशक के आरंभ में, स्वैच्छिक संगठनों से जुड़े उच्च शिक्षित और पेशेवरों के विकास में प्रगति और उन्नति हुई। कई नागरिक समाज संगठन अस्तित्व में आए और टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, ग्रामीण प्रबंधन संस्थान, भारतीय सामाजिक संस्थान और महिला अध्ययन केंद्र के साथ विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न रहे।

कई नागरिक समाज संगठनों की उच्च गुणवत्ता वाली प्रस्तुति ने उनके नेतृत्व वाले विभिन्न व्यक्तियों को स्वीकृति दी और सरकार ने उन्हें आधिकारिक समूह में शामिल करना आरंभ कर दिया। सामाजिक कार्य और अनुसंधान केंद्र (Social work and Research Centre-SWRC), तिलोनिया (Tilonia) के संजित बंकर रॉय एक अभिनव विचारक थे और प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान योजना आयोग के सलाहकार थे। अहमदाबाद में (Self Employed working Assocition – SEWA) की इला भट्ट (Ela Bhatt) को संसद के उच्च सदन के सदस्य के रूप में नामित किया गया था जिन्हें स्व–नियोजित महिलाओं के राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना ने जनभागीदारी नींव को बढ़ाने में सराहनीय कार्य पर बल देते हुए सरकार के कार्य–निष्पादन की पुनः संकल्पना की। इसने सिफारिश की कि लोगों के गतिशीलता में सुधार करना अनिवार्य है। शिक्षा, स्वास्थ्य, मानवाधिकार, पर्यावरण, परिवार नियोजन, भूमि–सुधार, कुशल भूमि उपयोग, जलविभाजक प्रबंधन, बंजर भूमि की प्रतिप्राप्ति, वनीकरण, पशुपालन आदि जैसे क्षेत्रों को जन संगठन द्वारा पूरा किया जा सकता है। उन्हें अच्छे सामुदायिक जीवन के लिए उत्तरदायी होना चाहिए। आठवीं योजना स्वैच्छिक संगठनों को लोक सेवाएं स्थापित करने और वितरित करने पर अधिक जोर देती है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र ने प्रमाणित किया कि कई स्वयंसेवी संगठनों के पास जमीनी स्तर पर कार्यक्रमों को लागू करने का एक सत्यापित दस्तावेज है और उन्होंने इस क्षेत्र में प्रेरक परिणाम दिखाए हैं।

वर्ष 2007 नागरिक समाज संगठनों की नव–उभरती भूमिका के लिए महत्वपूर्ण वर्ष था। योजना आयोग ने आधिकारिक तौर पर स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय नीति की स्थापना की है। समुदाय में आम आदमी के लिए एक निष्पक्ष, लोकतांत्रिक, स्वैच्छिक क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए योजना आयोग की ओर से यह आरक्षण बहुत नवीन था। नीति इस विश्वास को पुष्टि करती है कि स्वैच्छिक क्षेत्र, क्षेत्रों की बहुलता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। नागरिक समाज संगठनों की भागीदारी स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर निजी क्षेत्र के प्रयासों के कारण हुई। स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय नीति के उद्देश्य निम्नलिखित मापदंडों को दर्शाते हैं :

i) स्वैच्छिक संगठनों को भारत और विदेशों से आवश्यक वित्तीय संसाधनों को उचित रूप से प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करना;

ii) उन प्रणालियों को वर्गीकृत करने के लिए, जिनके द्वारा सरकार सामूहिक रूप से स्वैच्छिक संगठनों के साथ पारस्परिक विश्वास और प्रशंसा के दर्शन के आधार पर और सामान्य जवाबदेही के साथ काम कर सकती है;

iii) स्वैच्छिकता संगठनों को शासन और प्रशासन की स्पष्ट और जिम्मेदार प्रणालियों को स्वीकार करने के लिए विश्वास में लेना; और

iv ) स्वैच्छिक संगठनों के लिए सशक्त वातावरण बनाना, जो उनके उद्यम और प्रभावकारिता को प्रेरित करता है और उनकी स्वतंत्रता को बनाए रखता है।

आधिकारिक नीति ने नागरिक समाज संगठनों के साथ सरकार के संयुक्त उद्यम पर ध्यान केंद्रित करने पर भी अधिक जोर दिया। संयुक्त उद्यम कामकाज की तीन रचनात्मक गतिविधियों को स्वीकार करता है:

i) सम्मेलन;

ii) केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर इंटरफेस (पारस्परिक क्रिया); और

iii) परियोजना हेतु वित्तीय सहायता।

सरकार उपर्युक्त नीति के माध्यम से शासन में नागरिक समाज संगठनों की भूमिका को बढ़ावा देना चाहती थी।

भारत में नागरिक समाज संगठन अपने सर्वोत्तम प्रयास में निम्नलिखित पहलों की ओर अग्रसर हो रहे हैं। पहल निम्नलिखित में से हैं :

i) स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार;

ii) शैक्षिक सुधार;

iii) आर्थिक सुधार; और

iv) सामाजिक सुधार।

नागरिक समाज संगठन स्वास्थ्य के क्षेत्र में सभी ओर से पहल कर रहे हैं। ऐसे प्रयासों के लिए नए स्वैच्छिक संगठनों की आवश्यकता है जिससे लोक निजी संयुक्त उद्यमों के विचार का आरंभ हुआ। निजी क्षेत्र में लाभ और गैर–लाभकारी संगठन दोनों शामिल है। वर्तमान में, भारत के राज्यों में कई निजी भागीदारी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। कई नागरिक समाज संगठन भी सरकार के संचालन के साथ संयुक्त उद्यम में अस्पतालों को चलाने में सफल रहे है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में निरंतर कार्य करने के लिए रोगी कल्याण समिति, गैर–सरकारी संगठन (एन जी ओ) की स्थापना की गई थी। इस क्षेत्र के विभिन्न अस्पतालों को बढ़ावा देने के लिए अस्पतालों के समुदाय आधारित प्रबंधन की स्थापना की गई थी। RKS (आर के एस) को आधिकारिक तौर पर मध्य प्रदेश सामाजिक पंजीकरण अधिनियम 1973 के तहत पंजीकृत किया गया था। इस नागरिक समाज संगठन की जिम्मेदारी उनकी स्थानीय जरूरतों के लिए धन एकत्रित करना है। समिति लोगों की स्थानीय जरूरतों और अस्पताल की मूलभूत सेवाओं में सुधार के लिए संलग्न थी। इस प्रकार की व्यवस्थाओं का स्वास्थ्य सुधार पर सराहनीय सकारात्मक प्रभाव पड़ा। अन्य नागरिक समाज संगठन जैसे केरल में चिकित्सालय विकास समाज, राजस्थान में चिकित्सा राहत समाज, उत्तरांचल में चिकित्सा प्रबंधन समिति और अस्पताल कल्याण समिति स्वास्थ्य सुधार की दिशा में काम करने वाले कुछ उदाहरण हैं।

सभी को शिक्षा देने में सरकार का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रति जागरूकता भी गरीबों में संतोषजनक नहीं है। पिछड़े वर्ग को मूल शिक्षा

से वंचित रखा गया है। कई नागरिक समाज संगठन सरकार के रिक्तता अंतराल को भरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कई गैर–सरकारी संगठन (एन जी ओ) काम कर रहे हैं। कई नागरिक समाज संगठन क्षेत्रीय रूप से अवस्थित है। उनमें से कुछ की राष्ट्रीय पहुंच में अपनी विश्वसनीयता है। विश्व बैंक ने प्रारंभिक शिक्षा के विविध क्षेत्रों में कई नागरिक समाज संगठनों के कामकाज का प्रदर्शन सूचकांक (MV Foundation) भी दिया है। अधिकांश नागरिक समाज संगठनों ने अच्छे सामुदायिक जीवन के लिए सर्वोत्तम कार्यों के मॉडल को दोहराने और सुधारने के लिए अपनी स्वयं की कामकाजी परिस्थितियों को बढ़ावा देना आरंभ कर दिया। प्रथम मुबंई संघ, बोध शिक्षा समिति, ऋषि घाटी ग्रामीण शिक्षा केंद्र, एकलव्य और शिक्षा केंद्र प्रबंधन और विकास, एम वी संघ (MV Foundation) का मूल उद्देश्य और प्राथमिकताएं सामाजिक विकास है। एम वी संघ का आरंभ आंध्र प्रदेश में हुआ था। इसने एक ऐसी प्रतिकृति का शहरीकरण किया जो शिक्षा का उपयोग बाल श्रम के उत्तरदायित्व के साधन के रूप में करता है। इसने सरकारी स्कूलों के संचालन के साथ साझेदारी है। बच्चों के लिए शिक्षा के सर्वोत्तम कार्यों को करने के क्षेत्र में इनका कार्य सराहनीय रहा है। बाल श्रम के उन्मूलन के लिए एम वी (MV) ने एन एफ ई (NFE) कार्यक्रम को बढ़ावा दिया। एक अन्य नागरिक संगठन प्रथम मुंबई शिक्षा समिति ने प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के साधन के रूप में बचपन की शिक्षा आरंभ की। प्रथम, यह एक लोक धर्मार्थ ट्रस्ट है, जो यूनीसेफ (UNICEF) के सहयोग से पहल कर रही थी। सभी बच्चों को मुंबई शहर के स्कूलों में भेजने की कार्यसूची (एजेंडा) तय

की गई थी। मुंबई में पूर्वस्कूली सुविधाएं थीं। यह मुंबई में शहरी वंचित था जिनके लिए 3000 बालवड़ी (पूर्व स्कूली केंद्र) मुंबई की मलिन बस्तियों में चल रहे थे। प्रथम का एजेंडा 3–10 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना था। यह समुदायों के प्रति बहुत संवेदनशील था। बोध शिक्षा समिति के साथ अन्य नागरिक समाज संगठनों ने 1980 के दशक में अपना कामकाज आरंभ किया। यह विशेष रूप से जयपुर, राजस्थान में समुदाय में वंचित समूहों के लिए उपयुक्त शिक्षा के सर्वोत्तम कार्यों को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए आरंभ किया गया था। दोनों ने युवाओं को रोजगार दिया और बच्चों को स्कूलों में आने के लिए प्रेरित करने के लिए चल रहे स्कूल में कार्यरत युवाओं को प्रशिक्षण कौशल भी प्रदान किया।

कई गैर–सरकारी संगठन भी भारत में पर्यावरण शासन को बढ़ावा देने के लिए पहल कर रहे हैं। वे पर्यावरण संरक्षण के प्रति बहुत संवेदनशील है। विज्ञान और पर्यावरणीय केंद्र गैर–सरकारी संगठनों का जीवन उदाहरण है, जो विकास और स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार की दिशा में अथक प्रयास कर रहे हैं।

यह स्पष्ट है कि भारत में नागरिक समाज संगठन सरकार के प्रदर्शन के विकास के एजेंडे की निगरानी में बहुत ही उत्पादक अर्थात महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है।

**बोध प्रश्न 1**

**टिप्पणी** : (i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

(ii) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर मिलाइए।

1) ब्राजीलियाई नागरिक समाज स्वायत्तता और राजनीतिक निर्भरता के बीच कैसे उभरा?

.....

.....

.....

.....

.....

2) रूसी नागरिक समाज की बुनियादी विशेषताएं क्या है?

.....

.....

.....

.....

.....

2) भारत में नागरिक समाज संगठनों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

## 13.6 चीन में नागरिक समाज की बढ़ती भूमिका

चीन में नागरिक समाज संगठनों की भागीदारी बढ़ रही है। चीन में नागरिक समाज की भागीदारी आकार, संख्या और शक्तियों में बढ़ रही है। नागरिक समाज संगठनों की संख्या को सामाजिक संघ और निजी गैर–लाभकारी संघों (Non-Profit Associations-NPA) और नागरिक समाज संगठनों (Civil Society Organizations-CSO) के रूप में जाना जाता है। उनके पास विविध प्रबंधकीय व्यवस्था है। ये नागरिक समाज संगठन महिलाओं की समस्याओं, विकलांगों, उपभोक्ता संरक्षण के मुद्दों, वकालत के काम और सरकार से शासन तक से जुड़े हुए है। राष्ट्रीय विनियमन प्रणाली वर्ष 1989 में आरंभ की गई थी। चीन सरकार ने नए सामाजिक संगठनों की बढ़ती भूमिका की निगरानी के लिए इसे प्रयुक्त किया था। वर्ष 1998 में, राज्य परिषद ने संघों के पंजीकरण को प्रशासित करने के लिए मौजूदा विनियम को अपनाया।

विशेष वर्ष में राज्य परिषद ने निजी गैर–उद्यम इकाइयों के पंजीकरण के लिए विनियमन को भी वैध कर दिया। चीन में नागरिक समाज समूहों (सिविल सोसाइटी ग्रुप) को भी अंतर्राष्ट्रीय नागरिक समाज समूहों और दाता एजेंसियों से सहयोग और नैतिक समर्थन की आवश्यकता है। पश्चिमी गैर–सरकारी संगठन भी प्रभावी नागरिक

समाज कार्य के लिए एक प्रतिकृति प्रस्तुत करते हैं; और इस संबंध में एक मार्गदर्शक के रूप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह चीन में लोकतांत्रिक नैतिकता में नागरिक समाज समूहों को प्रोत्साहन और प्रेरक भावना थी। भागीदारी, समान अधिकार, जवाबदेही और खुलापन ऐसे आवश्यक मुद्दे हैं, जिन पर नागरिक समाज संगठनों द्वारा एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ध्यान केंद्रित किया गया है।

वर्तमान में, चीन के नागरिक समाज ने अच्छी तरह से निर्मित विकास के नए प्रतीकों का प्रदर्शन करना आरंभ कर दिया। आज चीन में पर्यावरण और जेंडर समानता के क्षेत्र में कार्य करने वाले विभिन्न गैर–सरकारी संगठन और अनौपचारिक समूह हैं। प्रत्येक चीनी महिला संघ अब सक्रिय और सामूहिक रूप से लोगों को चीन में सामान्य मुद्दे के लिए अपना नेटवर्क बढ़ाने के लिए एकत्रित करते हैं।

चीनी पर्यावरण समूहों ने भी नागरिक समाज के साथ सहयोग की निगरानी में गहरे संबंध निर्मित किए है। चीन में नागरिक समाज समूह (सिविल सोसाइटी ग्रुप) अब निम्नलिखित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं :

i) मानवाधिकार पर मुद्दें;

ii) कानूनी विकास पर मुद्दें;

iii) लोकतंत्रीकरण पर ध्यान; और

iv) पर्यावरण शासन पर ध्यान।

## नागरिक समाज की बढ़ती भूमिका और शासन पर इसका प्रभाव

चीन में नागरिक समाज की विकसित प्रकृति आधुनिक चीन की नींव का परिणाम है। वर्तमान में, आधुनिक चीन में 80,000 नागरिक समाज संगठन (सी एस ओ) कार्यरत हैं। वे प्रत्यक्ष रूप से चीन में शासन के घटकों में शामिल हो रहे हैं। चीन में सक्रिय जन संगठनों के रूप में श्रमिक संघ समूह, युवा संघ समूह और महिला संघ स्थापित किए गए हैं। चीन ने आर्थिक सुधार की नीति को क्रियान्वित करने का प्रयास किया, और शासन को बढ़ावा देने के लिए एक वैकल्पिक तंत्र खोजने का प्रयास किया। यह डेंग जियाओपिंग (Deng Xiaoping) के नेतृत्व में किया गया था। यह चीनी समाज के राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन और चीन में नागरिक समाज का उदय था। इसने चीन के इतिहास में पहली बार कई नागरिक संगठनों के विकास को प्रभावित किया। 1980 के दशक के अंत में, चीन ने बाजार–उन्मुख आर्थिक खुलेपन का आरंभ किया। इसने समाजवादी बाजार अर्थव्यवस्था की स्थापना की और यह राज्य के स्वामित्व से सामूहिक स्वामित्व की ओर एक स्थानांतरण प्रतिमान था। इसने चीन में आम लोगों के आजीविका के अधिकार को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया। यह चीन में नागरिक समाज संगठनों की बढ़ती भूमिका की आधारशीला थी।

## नया आर्थिक विन्यास और नागरिक समाज (New Economic Configuration and Civil Society)

इस नए आर्थिक विन्यास के अन्तर्गत, कई नागरिक समाज समूह, जैसे व्यापार संघ काफी हद तक सरकार से लेकर शासन तक अधिक लोकतांत्रिक और प्रभावी बन सकते हैं। चीन में नागरिक समाज संगठनों के निम्नलिखित इंटरफेस (Interface) का स्पष्ट रूप से अध्ययन किया जा सकता है :

i) बाजार आधारित विकास नागरिक समाजों के बीच एक कड़ी था। यह उद्यमों की जिम्मेदारी के जोखिम में था;

ii) बाजार अर्थव्यवस्था के स्थिर कार्यान्वयन ने मौलिक परिवर्तन को प्रभावित किया और विभिन्न प्रकार के जो स्वामित्व मौजूद थे, उन्हें भी प्रभावित किया;

iii) कई नागरिक समाज समूह विकसित हुए जो चीन में सेवा वितरण प्रणाली के लिए अपना स्वयं का धन एकत्रित करना चाहते थे;

iv) विभिन्न नागरिक समाज संगठनों की आवश्यक आर्थिक स्थिति और त्वरित संचालन के लिए मौलिक परिवर्तनों द्वारा अद्‌भुत खुलापन लाया गया;

v) प्रति व्यक्ति आय के आधार पर चीनी नागरिकों के आजीविका के अधिकार के मानकों को लगातार बढ़ाया गया है। यह कई नागरिक समाज संगठनों द्वारा विकसित सर्वोत्तम कार्यों के कारण था; और

vi) ग्रामीण और साथ ही शहरी निवासियों की प्रति व्यक्ति आय में भी 9 प्रतिशत से अधिक की औसत वृद्धि और क्षेत्र में नागरिक समाज के संचालन के कारण वृद्धि हुई।

खेल संघ, निजी सौहार्दपूर्ण संगठन (Private Amicable Organizations), यात्रा संघ और मनोरंजन क्लब आदि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और चीन में आम नागरिक के लिए आय सृजन गतिविधियों का भी प्रतीक है। चीन में, कई नागरिक समाज संगठनों को आर्थिक नींव और अनुकूल राजनीतिक वातावरण की आवश्यकता होती है जो परिवर्तनतों और विकास को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। 80 के दशक के अंत में चीन की सरकार ने स्वैच्छिक संघों को वैध बनाने के लिए कानूनी व्यवस्था और कानून के नियम के विकास पर ध्यान दिया। संघ की स्वतंत्रता को मान्यता दी गई। इसे चीन में नागरिक समाज के गठन के लिए मौलिक कानूनी आधार स्वीकार किया गया था। सरकार ने कई पूर्ण शक्तियों को जमीनी स्तर पर पारित किया। कार्यान्वयन की प्रक्रिया में, स्थानीय राजनीतिक व्यवस्था ने संवर्ग, प्रबंधकीय शक्तियों की तुलना में अधिक शक्तियों का प्रयोग किया। कई नागरिक समाज संगठनों के अत्यधिक दबाव के कारण, सरकार ने नागरिकों के प्रबंधन के कामकाज पर अधिकार कर लिया।

स्थानीय समुदाय स्तर पर नागरिकों को चीन के ग्रामीण क्षेत्र में लोक सेवा वितरण प्रणाली के लिए अपनी पसंद का कार्य करने का अधिकार था। यह स्वशासन मॉडल

के रूप में कार्य करता था जिसे ग्रामीणों द्वारा विकसित किया गया था। चीन के ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न ग्रामीण समिति  की स्थापना की गई थी और यह चीन के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत व्यापक नागरिक संगठन था। सरकार ने नागरिक मामलों, अकादमिक अनुसंधान और व्यवसाय के क्षेत्रों में कई कार्यों को उठाया, लेकिन दूसरी ओर सरकार ने गैर–सरकारी संगठनों को भी जमा धन के साथ इन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए कार्य सौंप दिए। चीन में पार्टी नागरिक समाज की उभरती भूमिका से युक्त है।

कई नागरिक समाज संगठनों ने सामाजिक कल्याण नीतियों की प्रक्रिया में सक्रिय भाग लिया। उन्होंने सरकार के प्रदर्श को बढ़ावा देने का प्रयास किया। सूंग चिंग लिंग फाउंडेशन, चाइना यूथ डेवलपमेंट फोरम, ऑल–चाइना सोसाइटी ऑफ चैरिटी (Soong Ching Ling Foundation, China Youth Development Forum, All China Society of Charity) इनमें से कुछ गैर–सरकारी संगठन हैं जो जरूरत के समय संकटग्रस्त महिलाओं की मूलभूत सहायता प्रदान करने में चीनी समाज में एक सराहनीय भूमिका निभा रहे हैं।

परियोजना विरोधी विकास रणनीति, प्रोजेक्ट होप के कार्यान्वयन ने युवाओं की सामाजिक छवि को बढ़ावा दिया। प्रोजेक्ट 'होप' को बच्चों को लाने और उन्हें स्कूल भेजने के लिए भी विकसित किया गया था। नागरिक संगठन ने भी धन जुटाने का प्रयास किया और उन लाखों बच्चों की सहायता की जो स्कूल जाने में असमर्थ थे।

इस विकास प्रतिमान को (Communist youth leaque Committee-CYLC) चीन की केंद्रीय समिति की सहायता से सहयोग मिला था। चीन युवा विकास संस्थान या फोरम गरीब से गरीब व्यक्ति के बड़े उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहा था। इसने कुछ सीमा तक सरकार की गतिविधियों पर भी नजर रखी।

## 13.7 दक्षिण अफ्रीका में नागरिक समाज की बढ़ती भूमिका

दक्षिण अफ्रीका में नागरिक समाज की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। 1990 के दशक से, कई नागरिक समाज संगठनों को अफ्रीकी समाज में भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान चलाने के लिए संगठित किया गया था। दक्षिण अफ्रीका के आम आदमी के भीतर आर्थिक न्याय लाने के लिए कई नागरिक समाज समूहों का यह बड़ा प्रयास था। भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई में नागरिक समाज समूहों को जुटाने के लिए भ्रष्टाचार विरोधी शिखर सम्मेलन की स्थापना की गई थी। यह मंच सर्व–समावेशी लोक सेवा भ्रष्टाचार विरोधी रणनीति को अपनाने के लिए बहुत नवीन था। 2005–08 से, भ्रष्टाचार विरोधी शिखर सम्मेलन अक्सर आयोजित किए जाते थे। लेकिन, दूसरी तरफ स्वैच्छिक समूहों ने समितियों के अध्ययन से प्रभावी ढंग से भाग लिया। सुशासन और अफ्रीकी सहकर्मी समीक्षा तंत्र पर दक्षिण अफ्रीका के प्रयास ने नागरिक समाज समूहों को दक्षिण अफ्रीका की राष्ट्रीय मुख्यधारा में लाने के लिए व्यापक रिपोर्ट दी।

2012 में, नागरिक समाज संगठनों सहित सामुदायिक समूह लगातार लगे हुए थे, और देश में भ्रष्टाचार को खत्म करने की दिशा में काम कर रहे थे। दक्षिण अफ्रीका में

लोकतंत्रीकरण को अपनाने के बाद से, बाहर के नागरिक समाज समूहों ने भी लोगों को भ्रष्टाचार के विरुद्ध काम करने के लिए प्रभावित और प्रेरित किया। उनके मजबूत लोकतांत्रिक समर्थन ने अफ्रीकी समाज में सार्वभौमिक दृश्यता ला दी। भ्रष्टाचार के विरुद्ध जाने के लिए कांगो (Congo) के नागरिक समाज का जुटाव भी समय की कसौटी पर खरा उतरा। नागरिक समाज संगठनों के विविध समूह दक्षिण अफ्रीका में हाशिए के लोगों (Marginalized) की सहायता करने के लिए बहुत ही गतिशील भूमिका निभा रहे हैं। रंगभेद कानूनों के तहत, लाखों गैर–श्वेत नागरिकों को उनके अधिकारों और अत्याचारी अधीनता के आधार पर वंचित किया गया था। लोगों को जमीनी स्तर (grattroot) की आवश्यकताओं पर प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने के लिए सरकार नागरिक समाज संगठनों को भी साथ लेकर आई। नागरिक समाज संगठनों ने जरूरतमंदों की सहायता करने के लिए सहभागितापूर्ण लोकतंत्र के निर्माण पर प्रकाश डालने का प्रयास किया।

सामुदायिक सलाह कार्यान्वयन क्षेत्र, परोपकारी विकास जैसे अन्य नागरिक समाज समूहों को भी गरीब और वंचित लोगों को मुक्त और पहुंच योग्य कानूनी सलाह, और इससे जुड़ी सेवाएं प्रदान करने, स्थानीय सामुदायिक विकास को बढ़ावा देने और समुदायों के प्रति स्थानीय सरकारों को जवाबदेह ठहराने में सहायता करने के लिए विकसित किया गया था। नेटवर्क को जोड़ने और आम लोगों का समर्थन करने के लिए वकालत के तरीके लागू किए गए।

दक्षिणी अफ्रीकी गैर–सरकारी संगठन गठबंधन (South African Non-Governmental Organization Coalition-SANCOGO), सामुदायिक विकास संसाधन संघ (Community Development Resource Association-CORA), मानवाधिकार संस्थान, सामाजिक परिवर्तन सहाय ट्रस्ट (Social Change Assistance Trust-SCAT), दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र संस्थान (IInstitute for Democracy in South Africa-IDASA), नागरिक समाज केंद्र (Civil for Civil Society-CCS), फोर्ड फांउडेशन (Ford Foundation), जैसे कई अन्य प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठन के सामाजिक पंजीकरण अधिनियम के तहत काम कर रहे है।

नागरिक समाज ने गुलामी विरोधी आंदोलन (Anti-slavery movenment) में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और महिला मताधिकार के बारे में बात करने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में नीति विकास में बहुत ही परामर्श की भूमिका निभाई। समूह अधिक प्रत्यक्ष रूप से समाज में नीति समर्थन और सेवा वितरण प्रणाली में संलग्न थे। दक्षिण अफ्रीका में नागरिक समाज वैश्विक प्रवृत्तियों और रंगभेद के प्रसार से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। रंगभेद के समय दक्षिण अफ्रीका में नागरिक समाज की स्थापना विशेष रूप से नस्ल, जातीयता और वर्ग पर आधारित थी। ये दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के समय वकालत के काम में संलग्न थे। उन्होंने गरीबों के लिए लड़ाई लड़ी और दक्षिण अफ्रीका के हाशिए के समूहों के जीवन में सुधार किया।

एकजुटता में कई नागरिक समाज समूहों ने मानव और नागरिक अधिकारों की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए निरंतर संघर्ष किया। कुछ नागरिक समाज समूहों ने कई मुद्दों, चुनौतियों और समस्याओं के अनुसार संघर्ष को संगठित किया। उन्होंने उच्च लगान, पर्यावरणीय घटाव, शहरी सेवाओं आदि पर ध्यान केंद्रित किया। राजनीति उथल–पुथल के समय, समस्याओं का राजनीतिकरण किया गया। नागरिक समाज समूहों ने भी अवैध सरकार की गतिविधियों की निगरानी की। अधिकांश रंगभेद विरोधी स्वैच्छिक समूह प्रामाणिकता और नियंत्रण के लिए अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस (ए एन सी) पर निर्भर थे।

दक्षिण अफ्रीका में 1994 में लोकतंत्र में परिवर्तन ने कई क्षेत्रों में नागरिक समाज समूहों की सफलता देखी। कई नागरिक समाज समूह भी सरकारी पद से व्यवसाय की ओर स्थानांतरित हो गए। इसका परिणाम शासन के विभिन्न क्षेत्रों में नागरिक समाज की गतिविधियों का पतन था। समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने में, मध्यम, बड़े और क्षेत्रीय रूप से केंद्रित समुदाय आधारित संगठन अब इसमें शामिल हो गए थे, जो संगठन पंजीकृत नहीं थे, वे भी अब इसका हिस्सा शामिल थे। दक्षिण अफ्रीकी समाज के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अभी भी उनकी गहरी भूमिका थी। स्वैच्छिक संगठन दक्षिण अफ्रीका में गरीबी कम करने की रणनीति के रूप में स्टोकवेल और सहकारी समितियों के गठन के लिए सक्रिय रूप से भाग लिया है।

विरोध की वैश्विक लहर ने दक्षिण अफ्रीका में गैर–सरकारी संगठनों के क्षेत्र में एक बड़े बदलाव को चिहिन्त किया। लोकतांत्रिक परिवर्तन के दौरान ए एन सी (ANC) के भीतर परिवर्तन लाने के लिए सामाजिक आंदोलन सक्रिय रूप से इससे जुड़ गए थे। सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2001 में आयोजित किया गया था। इस शिखर सम्मेलन में, सामाजिक आंदोलनों और विभिन्न सामुदायिक संगठनों ने कठोर संघर्ष किया और असमानता के बारे में बात की। लोक वस्तुओं के वितरण के मामले में ए एन सी की प्रतिबद्धता विफल रही। दक्षिण अफ्रीका में कई सक्रिय नागरिक समाज समूहों का त्रिपक्षीय गठबंधन था। निजीकरण विरोधी मंच की स्थापना की गई, और लोगों को बिजली और पानी की जांच के लिए प्रेरित किया।

रंगभेद के बाद दक्षिण अफ्रीका में सरकार ने नागरिक समाज समूहों का समर्थन किया। सेवा वितरण प्रणाली में सी एस ओ (CSOs) का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। इसने समाज में अपनी जिम्मेदारियों को फिर से परिभाषित करने के लिए सी एस ओ नागरिक समाज संगठन के कामकाज को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया। 1994 के बाद से नागरिक समाज (सिविल सोसाइटी) का पूर्व से परिवर्तित हो गया है। नागरिक समाज समूहों ने सरकार के साथ मध्य मार्ग पर आने के लिए संघर्ष किया। उनका वित्त–पोषण (फंडिग) पूर्ण रूप से सरकार पर निर्भर है। इस नए इंटरफेस में राज्य, नागरिक समाज और बाजार के बीच मान्यता दी गई थी।

दक्षिण अफ्रीका में मानवाधिकार आधारित (NGOs) एन जी ओ रक्षात्मक नागरिक अधिकारों को लेकर चिंतित हैं। यह सफल लोकतंत्र की दिशा में एक प्रयास था। संघ की एक उचित संख्या जो वंचित पड़ोसी को कानूनी और सामाजिक सेवाएं प्रदान करती है, देश भर में शैक्षिक संस्थानों में आधारित है। वे सामाजिक और आर्थिक निष्पक्षता के लिए अकादमिक और कार्यात्मक अनुसंधान का विलय करते हैं। एन जी ओ आम आदमी के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए अधिकार आधारित अभिविन्यास को प्रोत्साहित कर रहे हैं। यह प्रायः वकालत तकनीक से जुड़ा होता है और विविध सामाजिक न्याय अभियान के आसपास समुदायों को सक्रिय करने के लिए सशक्त होता है।

ए लॉयर फॉर हयूमन राइट्स (LHR) (Lawyer for Human Rights) दक्षिण अफ्रीका में संचालित स्वशासी गैर–सरकारी संगठन है और मानवाधिकारों के बारे में बहुत काम कर रहा है। मानवाधिकार सक्रियता के लिए सिविल सोसाइटी फॉर हयूमन राइट एक्ट विज्म एंड पब्लिक इंटरफेस लिटिगेशन नागरिक समाज और जनहित मुकदमेबाजी दक्षिण अफ्रीका में 35 वर्षों से कार्य कर रही है। यह संवेदनशील, वंचित और गरीब व्यक्तियों तथा समाज, गैर–राष्ट्रीय और दक्षिण अफ्रीकी पीड़ितों को उनके वैध अधिकारों के लिए मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करता है। यह वर्ष 1979 में संचालित किया गया था। संगठन ने रंगभेद के तहत मानव अधिकारों की अधीनता और दुर्व्यवहार का मुकाबला करने में एक आत्म–धार्मिक प्रमाण प्राप्त किया।

**बोध प्रश्न 2**

**टिप्पणी** : (i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

(ii) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर मिलाइए।

1) चीन में नागरिक समाज संगठनों बढ़ती भूमिका का परीक्षण कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

2) दक्षिण अफ्रीका में कार्यरत प्रमुख नागरिक समाज संगठनों के कार्य समझाइए?

.....

.....

.....

.....

.....

## 13.8 निष्कर्ष

ऐसा कहा जाता है कि ब्रिक्स में नागरिक समाज संगठनों का उदय विश्व–भर में लोकतंत्रीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण घटना रही है। ब्रिक्स देशों में नागरिक समाज को अपनी सामाजिक स्वतंत्रता का विस्तार करना होगा, और प्रशासनिक तंत्र के किसी भी अपवाद के मामले में राज्य से निपटने के लिए खुद को मजबूत करना होगा। ये सभी उपाय राज्य के कठोर परिश्रम के माध्यम से बाजार प्रक्रियाओं के अनुकूल है। समझा जाता है कि राज्य नागरिक समाज की स्थापना के समर्थन में एक उत्साहजनक भूमिका निभाता है। सभी ब्रिक्स देशों में राज्य एक संस्थागत रंगमंच प्रदान करता है, जिसके भीतर नागरिक समाज पनप सकता है और विकसित हो सकता है।

## 13.9 शब्दावली

**लोकतंत्रीकरण** : यह कानून के नियम के माध्यम से देश में लोकतांत्रिक सिद्धांतों की स्थापना का प्रतीक है।

## 13.10 संदर्भ लेख


Bophela, M.J.K. & Khumalo N. (2019). *The role of Stokvel in South Africa: A case of economic transformation of a municipality.* Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/336901920

Carver, T. & Bartelson, J. (ed.). (2011). Globality, *Democracy and Civil Society in India*. London: Routledge.

Graham, L. & Himlin, R. (2016). *National Development Agency Review of the State of Civil Society Organizations in South Africa, National Development Agency*.

Houtzager, P. Gurza Lavalle, A. and Charia, A. (2003). Who participates? Civil society and the new democratic politics in São Paulo, Brazil. Retrieved from https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/20.500.12413/4005/Wp210.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Keck, M. E. (1989). The new unionism in the Brazilian Transition. In Alfred Stepan (ed.) *Democratizing Brazil: Problems of Transition and Consolidation*. New York: Oxford University, Press.

Mersiyanova, I.V. (2009). Social base of Russian Civil Society. *Social sciences and modern times*. 4, 35–45.

Mezhuev, V. M. (2008). Civil society and modern Russia. In *Man and culture in formation of civil society in Russia*. Moscow: RASPI.

Nandini, D. (2017). Unit 09 Role of Civil Society Organisation in Policy-Making. In *MPA 015 Public Policy and Analysis*. Retrieved from https://egyankosh.ac.in/bitstream/123456789/25782/1/Unit-9.pdf

O'Bian K. J. Villagers, Elections and citizenship in Contemporary China. *Modern China.* 27(4), 407-435.

## 13.11 बोध प्रश्नों के उत्तर

**बोध प्रश्न – 1**

1) आपके उत्तर में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए :

- ब्राजील का नागरिक समाज स्वायत्तता और राजनीतिक निर्भरता के बीच एक बहुत ही गतिशील और अग्रणी भूमिका के रूप में उभरा। इसे एक नए संस्थान के रूप में देखा जाता है और दो प्रक्रियाओं की सहायता से बनाया जाता है।
- आधुनिकीकरण की अलोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति लोकप्रिय क्षेत्रों का प्रतिक्रियाशील व्यवहार।
- लोक नीतियों के कार्यान्वयन में राज्य से प्रभावी रूप से जुड़े संघों के समूहों का गठन।

- ब्रिक्स नागरिक समाज गोलमेज सम्मेलन के लिए एक नई वेबसाइट अक्टूबर 2014 में आरंभ की गई थी। यह सिविल ब्रिक्स को 2015 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के अधिकार क्षेत्र में पहली बार प्राप्त किए जाने वाले 'अभूतपूर्व राजनीतिक पाठ्यक्रम को दर्शाता है।

2) आपके उत्तर में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए :

- रूस में नागरिक समाज समूहों की मूलभूत विशेषताएं निम्नलिखित संकेतकों को दर्शाती हैं :
  - **नागरिक कार्य** : सामाजिक और राजनीतिक संगठनों में व्यक्तिगत विचार–विमर्श की तीव्रता।
  - **संगठन का चरण** : संस्थागत की सीमा, जो नागरिक समाज के गठन को दर्शाती है।
  - **मूल्यों का पालन करना** : जिस सीमा तक नागरिक समाज को सकारात्मक मूल्यों को आत्मसात करने और प्रतिबिंबित करने के लिए देखा जाता है।
  - **प्रभाव का अवलोकन** : आंतरिक और बाहरी जागरूकता दोनों के अनुसार, नागरिक समाज का स्पष्ट सामाजिक और नीतिगत झटका।
  - **पर्यावरण का बाहरी प्रभाव** : यह सामाजिक–राजनीतिक सांस्कृतिक स्थितियों को संदर्भित करता है। यह नागरिक समाज की गतिविधि की सीमा को संदर्भित करता है।

3) आपके उत्तर में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए :

- भाग 13.5 देखिए।

**बोध प्रश्न – 2**

1) आपके उत्तर में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए :

- भाग 13.6 देखिए।

2) आपके उत्तर में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए :

- दक्षिणी अफ्रीकी गैर सरकारी संगठन गठबंधन (SANCOGO) जैसे कई अन्य प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठन।
- सामुदायिक विकास संसाधन संघ (CORA)
- मानवाधिकार संस्थान, सामाजिक परिवर्तन सहाय ट्रस्ट (SCAT)
- दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र के लिए संस्थान (IDASA)
- नागरिक समाज केंद्र (CCS)
- फोर्ड फाउंडेशन, सिविकुस आदि गैर–सरकारी संगठनों के समाजिक पंजीकरण अधिनियम के तहत काम कर रहे हैं।

# इकाई 14 शासन में प्रशासनिक सुधार*

## इकाई की रूपरेखा


14.0 उद्देश्य

14.1 प्रस्तावना

14.2 ब्राजील में प्रशासनिक सुधार

14.3 रूस में प्रशासनिक सुधार

14.4 भारत में प्रशासनिक सुधार

14.5 चीन में प्रशासनिक सुधार

14.6 दक्षिण अफ्रीका में प्रशासनिक सुधार

14.7 निष्कर्ष

14.8 शब्दावली

14.9 संदर्भ लेख

14.10 बोध प्रश्नों के उत्तर


## 14.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात, आपः


* डॉ मीनाक्षी मदान, सहायक प्रोफेसर,, लोक प्रशासन, पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज, सेक्टर–46, चंडीगढ़

- ब्रिक्स देशों के शासन में प्रशासनिक सुधारों की प्रमुख उपलिब्धयों को समझ सकेंगे; तथा
- शासन में विभिन्न आयोगों और प्रशासनिक सुधार समितियों की भूमिका को जान पाएगें।

## 14.1 प्रस्तावना

प्रशासन कभी स्थिर नहीं रह सकता; बदलते समय के साथ इसे बदलना होगा। समाज बदलता रहता है, इसलिए प्रशासन भी ऐसा करता है और ये बदलाव नियोजित या अनियोजित हो सकते हैं। अनियोजित परिवर्तन समय और प्रथाओं के साथ विकसित होते हैं और प्रायः इसे कम करके आंका जाता है, जबकि प्रशासन में नियोजित परिवर्तन मौजूदा प्रणालियों, कार्यविधियों और प्रक्रियाओं में सुधार के लिए विचारपूर्वक या सचेत प्रयास करते है। इनके बारे में अच्छी तरह से विचार किया जाता है और इनके भले–बुरे का मूल्यांकन करने के बाद इन्हें अपनाया जाता है। ब्रिक्स देशों ने प्रशासनिक सुधारों के लिए सोच के वृद्धिशील और क्रमिकवादी अभिनव अभिविन्यास को अपनाया है। ब्रिक्स देशों में प्रशासनिक सुधार समय की जरूरत है, क्योंकि ये देश आने वाली विश्व अर्थव्यवस्थाएं है जो बहुत सक्रिय, नागरिक अनुकूल और व्यापक है। ब्रिक्स राष्ट्र प्रशासनिक सुधारों के बारे में नहीं सोच सकते है और वे शिष्टाचार रहित और अविवेकी है। प्रशासनिक सुधारों को व्यवस्था के अनुकूल और जनता के लिए उपयोगी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि देशों को स्थानीय परिस्थितियों के

अनुकूल सुधारों को तैयार करने और लागू करने के लिए व्यापक अभ्यास करना चाहिए।

## 14.2 ब्राजील में प्रशासनिक सुधार

प्रांरभिक प्रशासनिक सुधार 1930 के दशक के दौरान एक तानाशाही प्रशासन द्वारा ग्रहण किया गया था। यह आर्थिक और सामाजिक क्रांति के कारण नवीनीकरण की एक बढ़ती हुई प्रक्रिया थी। देश कृषि अर्थव्यवस्था से औद्योगिक अर्थव्यवस्था में बदल गया। इतिहास के गुजरते दौर के दौरान, ब्राजील में लोक प्रशासन की अवधारणा सार्वजनिक या लोक अधिकारी वर्ग के पारंपरिक मॉडल से दूर थी। प्रशासनिक सुधार का उद्देश्य विशेषज्ञता वाले अधिकारी–वर्ग के साथ–साथ राज्य की निरकुंश भूमिका को आगे बढ़ाना है। यह विकास के वेबेरियन मॉडल पर आधारित था। सरकार ने नई प्रबंधकीय प्रणाली की स्थापना की जो तकनीकी कौशल के मामले में कुशल और विशेषता वाले नौकरशाहों की भर्ती करती थी। प्रमुख प्रक्रिया लोक सेवा और बजटीय प्रक्रिया के युक्तिकरण के लिए प्रयास करना था।

ब्राजील ने वर्ष 1967 में एक और तानाशाही सरकार के दौरान आगामी मुख्य प्रशासनिक सुधार का अभ्यास किया। सुधार ने संघीय सरकार के ढांचे और परिचालन मोड को बदलने के लिए सबसे व्यवस्थित और निर्धारित परियोजना को मापा। कुल मिलाकर, राजाज्ञा (Decree) कानून का उद्देश्य संघीय लोक प्रशासन के संगठन को फिर से परिभाषित करना था। पुनःगठन चार प्रमुख सिद्धांतों पर असहाय था :

- समानीकरण
- प्रबंध
- प्रशिक्षण
- विकेंद्रीकरण

सैन्य शासन के अंत, लोक प्रबंधन में एक और सुधार करने का प्रयास किया गया था। लोक क्षेत्र को अधिक गतिशील बनाने के लिए लागू किए गए संगठनात्मक मानदंडों और नियमों को कम करने के लिए सुधार सूचनात्मक था। हालांकि जो पहल की गई थी उसका अपेक्षित परिणाम नहीं मिला और सुधार अंततः विफल रहा। लोक प्रबंधन के सुधार की विफलता के बाद, 80 के दशक में लोकतांत्रिककरण प्रक्रिया की दृश्यता दिखाई दी, जिसने 1988 के संघीय संविधान की समाप्ति को चिहिन्त किया। सत्ता के हस्तांतरण, लोगों की भागीदारी और सामाजिक सुरक्षा योजना के सार्वभौमिक मानक के लिए प्रयास करने पर लोकतंत्रीकरण के आधार पर दिशानिर्देशों को निष्पादित किया गया था। व्यवस्था के तहत, सिविल सेवा स्थिरता सुधार का एजेंडा था।

संबंधित क्षेत्रों में, नए लोक प्रबंधन दिशानिर्देश पहले कार्डोसो प्रशासन (First Cordoso Administration) में संघीय सरकार के साथ एकीकृत हुए जो 1995–1998 तर जारी रहे। सुधार प्रक्रिया का मार्गदर्शन करने के लिए असाधारण विभाग की स्थापना की गई थी। कार्यक्रम आरंभ किया गया था और लोकप्रिय रूप से Plan Diretor Reforma do Aparelho do Estado कहा जाता था। सुधार का एजेंडा निम्न दिया गया है :

i) राज्य के शासन को बढ़ावा देना;

ii) लोक सेवाओं को नागरिकों को वापस करने के लिए कुशलतापूर्वक शासन करने के लिए प्रशासनिक क्षमता की स्थापना;

iii) विभिन्न वांछनीय कार्यों में राज्य गतिविधियों की अधोगति करना;

iv) राज्यों और नगरपालिकाओं के लिए लोक नीतियां नियुक्त करना; और

v) राष्ट्रीय नीतियों के संघ से राज्यों को प्रांतीय नीतियों और क्षेत्रीय नीतियों का स्थानांतरण।

निजी स्वामित्व वाले क्षेत्रों की सुविधा और विकेंद्रीकरण के सामाजिक विकास को विनियमित करने के लिए निजीकरण के प्रयास को बहुत प्रभावी बनाया गया था। कुछ चीजें प्रत्यक्ष रूप से योजना और बजट को विकेंद्रित करने से संबंधित थी।

अनुगामी वर्षों में ब्राजील ने 2003 में लेबर पार्टी नामक एक वामपंथी पार्टी के साथ सरकार के परिवर्तन का अनुभव प्राप्त किया। इसे राजनीतिक प्रशासनिक विकास के रूप में देखा गया। लेबर पार्टी प्रशासन के तहत उल्लेखित प्रमुख सुधार एजेंडा निम्न दिया गया है :

i) सामाजिक सशक्तिकरण और स्थानीय शासन को शक्ति का हस्तांतरण;

ii) लोक सेवाओं में निजीकरण की सुविधा;

iii) पेंशन प्रणाली सुधारों का पुनर्गठन; और

iv) सिविल सेवा पुनःसंगठन का पुनःर्गठन (जीविका करियर) का विविधीकरण, राज्य के विकास की स्पष्ट रणनीति।

इस सुधार का मूल उद्देश्य वर्तमान सरकार में की गई भागीदारी, नीति मूल्यांकन और जवाबदेही के संदर्भ में प्रशासनिक सुधार के बारे में बात करना है। विकास के केंद्र में आरंभ हुई तबाही के कारण राज्य के उपकरणों के पुनर्गठन के लिए प्रशासनिक सुधार की आवश्यकता है। यह चरण पेट्रोलियम की आपदा से आरंभ हुआ था। उस आपदा ने राज्य की विशालता की तीन समस्याओं को उजागर किया।

- आर्थिक समस्या;
- सामाजिक समस्या; और
- प्रशासनिक समस्या।

लागत–प्रभावी कार्य में, ब्राजील के समाज की स्थिति यह थी कि लागत–कटौती उपाय में राज्य की बहुत अधिक भागीदारी थी। सामाजिक क्षेत्र में प्रतिदिन लोक व्यय का अधिभार था, जिससे उन परिचालन खर्चों में कमी आई (न केवल एक सामाजिक, लेकिन नागरिक निर्धारित लागत, सामान्य रूप से, संक्षिप्त करने की आवश्यता थी)। प्रशासनिक तंत्र में, अधिकारी–वर्ग का बेवेरियन मॉडल, अवैयक्तिकता, तटस्थता,

तर्कसंगतता के रूप में अपनी विशिष्टता के साथ, ब्राजील के प्रशासन में कभी भी पूर्ण रूप से जीवित नहीं रहा।

80 के दशक में, राष्ट्रपति जोस सर्नी (Jose Sorney) ने सुधार करने का प्रयत्न आरंभ किया, लेकिन परिवर्तन की वास्तविक उपलब्धि नहीं थी। सरकार के राज्य फर्नांडों हेनरिक कार्डोसो (Fernando Henrique Cardoso) के सुधार का विकास 1995 में आरंभ हुआ। यह पुनर्गठन मॉडल अधिकारी–वर्ग को जीतने का एक प्रयास है। ब्राजील की नगरपालिका सरकार की पृष्ठभूमि पितृसत्तात्मकता का संकर नस्ल मॉडल है।

90 के दशक के आरंभ में, संरचनात्मक समायोजन का विचार एक महत्वपूर्ण प्रमुख उद्देश्य बना रहा और राज्य के पुनर्गठन या सुधार के लिए विचार किया गया, जिसे तथाकथित प्रशासनिक सुधार कहा जाता था। राज्य का प्रमुख उद्देश्य वैश्वीकरण की विश्व सेटिंग में राज्य की पुनः अवधारणाओं का निर्माण करना है। ब्राजील में संघीय प्रशासन और राज्य के सुधार मंत्रालय ने प्रशासनिक सुधार के तीन उद्देश्यों की सिफारिश की। इन पर निम्न चर्चा की जाएगी :

i) राज्य के विस्तार की फिर से कल्पना करना समय की मांग है। मूल उद्देश्य बाजार के स्थिर दिशा–निर्देश में राज्य के कार्यों को बढ़ावा देना, और सामाजिक गतिविधियों को सुविधाजनक बनाना है;

ii) पुनर्गठन का उद्देश्य राज्य की प्रशासनिक क्षमता को बढ़ाना है। समय की मांग थी कि लोक प्रशासन का आधुनिकीकरण किया जाए और जनता के लिए कायापलट में उत्कृष्टता और क्षमता की तलाश की जाए; और

iii) इसका उद्देश्य राजकोषीय नीति के समायोजन को बढ़ावा देना है। यह ब्राजीली राज्य के शासन को बढ़ावा देने का विकासात्मक उद्देश्य है।

**प्रशासनिक सुधारों का नौकरशाही और उत्तर–नौकरशाही मॉडल**

सुधार का पिछला प्राप्त अनुभव सफल नहीं रहा। नौकरशाही और उत्तर–नौकरशाही मॉडल के ब्राजीली सुधार के सैद्धांतिक नियमन ने प्रत्यक्ष रूप से DASP और Decreto-IIe 200 को प्रभावित किया। DASP वर्ष 1936 में आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य प्रशासन के नैतिक मानकों के सरलीकरण को प्राप्त करने के माध्यम से युक्तिकरण पर था। यह वैज्ञानिक प्रशासनिक सिद्धांत के उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट किया गया था। दूसरी आरे Decreto-IIe 200 का उद्देश्य 1967 के ब्राजीली राज्य का विकेंद्रीकरण करना था। तब ब्राजील में लोक प्रशासन के अनुशासन में नौकरशाही मॉडल का प्रभुत्व हो गया था। यह प्रशासनिक विकास का बहुत ही आदर्श मॉडल था। शासन में प्रशासनिक सुधार के वेबेरियन मॉडल के तहत कुछ नियमों का पालन किया गया था : ये इस पर आधारित है :

- सुव्यवस्थित रोजगार सृजन;

- वैध प्राधिकार के साथ श्रेणीबद्ध व्यवस्था की स्थापना;
- पेशेवर विशेषज्ञता और कौशल के आधार पर भर्ती; और
- आयु के आधार पर निर्धारित कार्यकाल।

राज्य के वर्तमान दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, ब्राजील में सरकार से शासन में परिवर्तन किया गया है। नौकरशाही मॉडल अब अप्रचलित हो गया है। राज्य की समस्याओं को दूर करने के लिए प्रशासन की गतिविधियों में नौकरशाही के बाद के प्रतिमान का अब प्रभुत्व हो गया है। पोस्ट–नौकरशाही मॉडल की निगरानी निजी क्षेत्र से की जा रही हैं। इस मॉडल ने प्रशासन के कामकाज में सकारात्मक लाभ दिया।

**साधारण कानून**

प्रशासन में विभिन्न प्रथाओं की बुराइयों को दूर करने के लिए साधारण कानून को क्रियान्वित किया गया था। कानून का उद्देश्य प्रस्तावित संशोधनों की पुष्टि करना था। कानून में ब्राजील में एक सुधार प्रक्रिया के रूप में कार्य किया था। यह सुधार की आवश्यकता की निम्नलिखित रूपरेखाओं से संबंधित है।

- राज्य सत्ता का समेकन;
- सिविल सेवकों की अतिरिक्त भूमिका को पद से हटाना;
- कार्मिकों की न्यायिक स्थापना की विविधता;
- सिविल सेवकों के लिए सामाजिक सुरक्षा की नई प्रणाली;

- तुलनात्मक पारिश्रमिक;
- सेवानिवृत की आयु;
- लोक नीतियों में सामजिक योगदान; और
- प्रशिक्षण की राष्ट्रीय नीति का कार्यान्वयन।

**मानव संसाधन**

मानव संसाधन ब्राजील में सुधार प्रक्रिया का एजेंडा भी है। मानव संसाधन विभाग की प्रमुख जिम्मेदारी पर्याप्त प्रशिक्षण देना और कर्मियों की भर्ती करना है। मानव संसाधन विभाग या HRD की स्थापना से लोक क्षेत्र में रोजगार बाजार को सुविधा मिलेगी।

**वित्त स्थान में सुधार : राज्य पेंशन सुधार**

इस परियोजना की योजना राज्यों की कार्यकारी शाखा पेंशन रजिस्ट्रियों के सुधार को बढ़ाने के लिए बनाई गई थी – पहली राज्य पेंशन आधुनिकीकरण परियोजना द्वारा वित्तपोषित। सरकारों ने पाठ्यक्रम में भाग लिया और लोक कर्मचारियों के लिए अपने पेंशन डेटा को वैध बनाने में सक्षम थे, जिससे बेईमानी और रिश्वत–खोरी में गिरावट के माध्यम से वांछित वित्तीय स्वतंत्रता पैदा हुई।

**नव लोक प्रबंधन**

नई लोक प्रबंधन (NPM) प्रणाली के आरंभ के साथ, प्रशासनिक विकास ने ब्राजील में सुधार प्रक्रिया की फिर से अवधारणा की है। यहां राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन है, जिसने प्रशासन में प्रक्रिया को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। NPM के कुछ मापदंडों के आधार पर, विकास की गतिशीलता के सामाजिक–आर्थिक संकेतकों की पुष्टि की गई है। ब्राजील में आम आदमी के बड़े उद्देश्यों को पूरा करने के लिए लोक सेवाओं की गुणवत्ता और पारदर्शिता को प्रभावी ढंग से वितरित किया गया। राजकोषीय मोर्चे से निश्चित वास्तविक योजना घटकों के साथ वैध रूप से मौद्रिक स्थिरता योजना को स्थापित किया गया। पूर्व–सुधार युग में, सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट थी। लेकिन NPM की कार्यान्वयन प्रक्रिया के बाद, प्रभावी लोकतांत्रिक नीतियों को निष्पादित करने के लिए जी डी पी (GDP) में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। और यह मध्यम वर्ग के विकास के अधीन भी है। NPM, 1995 के साथ अंतरराष्ट्रीय शक्ति के बाहरी प्रभाव के कारण, ब्राजील में संघीय सरकार ने शासन में राज्य की गतिविधियों को कम करने वाले राज्य उपकरण (Directive Plan for the Reform of the State Apparatus-PDRAE) के सुधार के लिए निर्देशक योजना शुरू की। इसका उद्देश्य कुछ सरकारी क्षेत्रों का निजीकरण करना था।

पोस्ट–एन पी ए (NPA) (तीसरी पीढ़ी के सुधार) को भी निम्नलिखित तरीकों से दर्शाया जाता है।

**तालिका 14.1: ब्राजील में पोस्ट–एन पी ए प्रशासनिक सुधार**

| उद्देश्य | कार्यकर्ता | प्रमुख क्षेत्र |
|---|---|---|
| सहयोग | लोक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और तीसरे क्षेत्र के भीतर भूमिका निभाना | संयुक्त भागीदारी |
| नेटवर्किंग | निष्पादन और कार्यान्वयन के लोक सेवाओं के साथ भूमिका निभाना | प्रशासन के साथ नेटवर्किंग संयोजकता की खोज |
| संयुक्त और समग्र संगठन की उन्नति | पर्यवेक्षण का प्रशासनिक दृष्टिकोण | सरकार की निरतरता |
| जवाबदेही | लोक प्रशासन समाज के प्रति खुलापन | सरलता |
| भागीदारी और संगठनात्मक प्रतिबद्धता | नीति कार्यान्वयन में सामाजिक भागीदारी का विकास | सहभागी लोकतंत्र की शक्ति और वितरण |
| नेतृत्व | लोक पर्यवेक्षण में राजनीतिक और प्रशासनिक प्रक्रिया | सामरिक निगरानी |
| ई–सरकार और सूचना और संचार | त्वरित सेवा के लिए नागरिकों की भागीदारी | डिजिटल शासन |

नव केंद्र लोक प्रबंधन (NPM) ने गुणात्मक सॉफ्टवेयर के मामले में बेहतर शासन को बढ़ावा देने के लिए लोक प्रबंधन की नई खोज का संघीय पुरस्कार (FAPMI) की परियोजना को मान्यता दी। ब्राजील सरकार ने प्रशासन के सुचारू कामकाज के लिए

अग्रणी प्रबंधकीय नियमों और आचार संहिता को स्वीकार किया। ब्राजील में प्रशासनिक सुधार के सर्वोत्तम अभ्यास मॉडल के तहत भागीदारी बजट भी आ रहा है।

25 पाठ्य पुस्तकें और 59 लेख प्रशासनिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए परिचलित किए गए जैसे शासन, नव लोक प्रबंधन और लोक प्रबंधन सुधार। यह तुलनात्मक विश्लेषण और विशिष्ट चयनित देशों के मामले के अध्ययन पर आधारित था। प्रदर्शन प्रबंधन की अवधारणा भी सुधार के एजेंडें में जारी रही। प्रशासनिक विकास के लिए निर्धारित पहले के एजेंडे का मूल्यांकन करने के लिए तीसरी पीढ़ी के सुधार भी श्रेष्ठ हो गए हैं।

## 14.3 रूस में प्रशासनिक सुधार

रूस में लोक प्रशासन में सुधार करने का धीमा और स्थिर प्रयास था। यह सोवियत संघ के विघटन के बाद से स्पष्ट था। 1992 के आरंभ में, रूसी संघ में सिविल सेवा के लिए कानूनी आधार बनाया गया था। 1995 में, एक संघीय कानून को क्रियान्वित किया गया था। इस कानून का कार्यान्वयन योग्यता और कौशल के आधार पर रूसी सिविल सेवा की दिशा में एक नया कदम था। संघीय कानून ने लोक प्रशासन के मुद्दों से संबंधित कई प्रोटोकॉल भी स्थापित किए। लेकिन किसी तरह यह सफल नहीं हो सका। 1997–1998 के दौरान, रूसी अधिकारियों ने प्रशासनिक सुधार के एक नए विचार पर चर्चा करने का प्रयास किया। लेकिन दूसरी ओर राष्ट्रपति पुतिन लोक

प्रशासन में सुधार के लिए एक पुनः अवधारणात्मक मांग के लिए प्रयास करना चाहते थे। इस अभिनव सुधार को *तीन* प्रमुख भागों में विभाजित किया गया थाः

i) सिविल सेवा सुधार में नवाचार;

ii) प्रशासनिक सेवा सुधार की स्थापना; और

iii) नगरपालिका संबंधी सरकारी सुधार।

**सिविल सेवा सुधार में नवाचार**

रूसी संघ ने 2001 में लोक सेवा के विचार को क्रियान्वित करने का प्रयास किया जिसे रूसी राष्ट्रपति द्वारा आरंभ किया गया था। सरकारी एजेंसियों में लोक सेवा विनियमन और मानव संसाधन प्रबंधन के लिए नए दृष्टिकोण स्थापित करने का प्रस्ताव था। रूसी संघ में लोक सेवा सुधार 2002 में रूस में प्रशासन के सुचारू संचालन के लिए स्थापित किया गया था। इस संबंध में, रूस में प्रशासनिक प्रक्रिया के पुनर्गठन के लिए संघीय कानून भी लागू किए गए। संघीय कानून द्वारा दिए गए कथन में, रूस में लोक सेवा प्रणाली में नौकरशाह (रूसी सिविल सेवा), पुलिस सेवा और अर्ध–सैन्य सेवा शामिल है। वर्ष 2004 में, रूसी संघ में सिविल सेवा लागू की गई थी। रूस में प्रशासनिक जवाबदेही के लिए सिविल सेवा पर अलग–अलग एजेंडा तय किया गया थाः

i) सिविल सेवकों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता का तरीका;

ii) सिविल सेवकों के लिए आरामदायक नौकरी में वृद्धि;

iii) सरकारी एजेंसियों के लिए पारिश्रमिक कोष की स्थापना; और

iv) समाधान तंत्र प्रक्रियाओं का निर्धारण।

## प्रशासन में पुनर्गठन कार्यक्रम

प्रशासन के पुनर्गठन कार्यक्रम को 2003 में रूस में राष्ट्रपति की आज्ञा द्वारा निष्पादित किया गया था। रूस में सरकार के लिए आयोग की स्थापना की गई थी। प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए दो विचारों को रेखांकित किया गया है:

1) अच्छे मंच पर सरकार की गतिविधियों का मूल्यांकन करना प्रमुख जिम्मेदारी है; और

2) तीन प्रकार के कार्यों को स्पष्ट तौर पर अलग करना आवश्यक है। इनकी चर्चा निम्न दी गई है :

   क) कानूनी कार्य के समुच्चय की व्यवस्था करना;

   ख) कार्यों के नियमों को कार्यान्वयन करना; और

   ग) कार्यों के नियमों को लागू करना।

वर्ष 2004 में, राष्ट्रपति की आज्ञा से संघीय कार्यकारी अधिकारियों की स्थापना के लिए सिफारिश की। सरकारी एजेंसियों की भूमिका में बहुत कमी आई है। कानूनी कार्य के समुच्चय की व्यवस्था करने का कार्य भी राज्यनीति के लिए जिम्मेदार है। मंत्रालयों की जिम्मेदारी नीति विश्लेषण का पालन करना और कानून के मसौदे को सक्षम बनाना है। सेवाएं भी पर्यवेक्षण के लिए समान रूप से उत्तरदायी है। वे राष्ट्रीय रक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और अपराध गश्त से संबंधित है। विभिन्न सरकारी विभागों से निकलने वाली एजेंसिया भी लोक सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए जवाबदेह हैं। प्रशासनिक सुधार की अवधारणा को रूसी संघ में वर्ष 2006–08 के दौरान लागू किया गया था। निम्नलिखित सारणी रूस में प्रशासनिक सुधार के घटकों का प्रतिनिधित्व करती है।

**सुधार की भावना :** रूस में सरकारी दिनचर्चा की निगरानी के लिए उपरी प्रणाली और उपाय

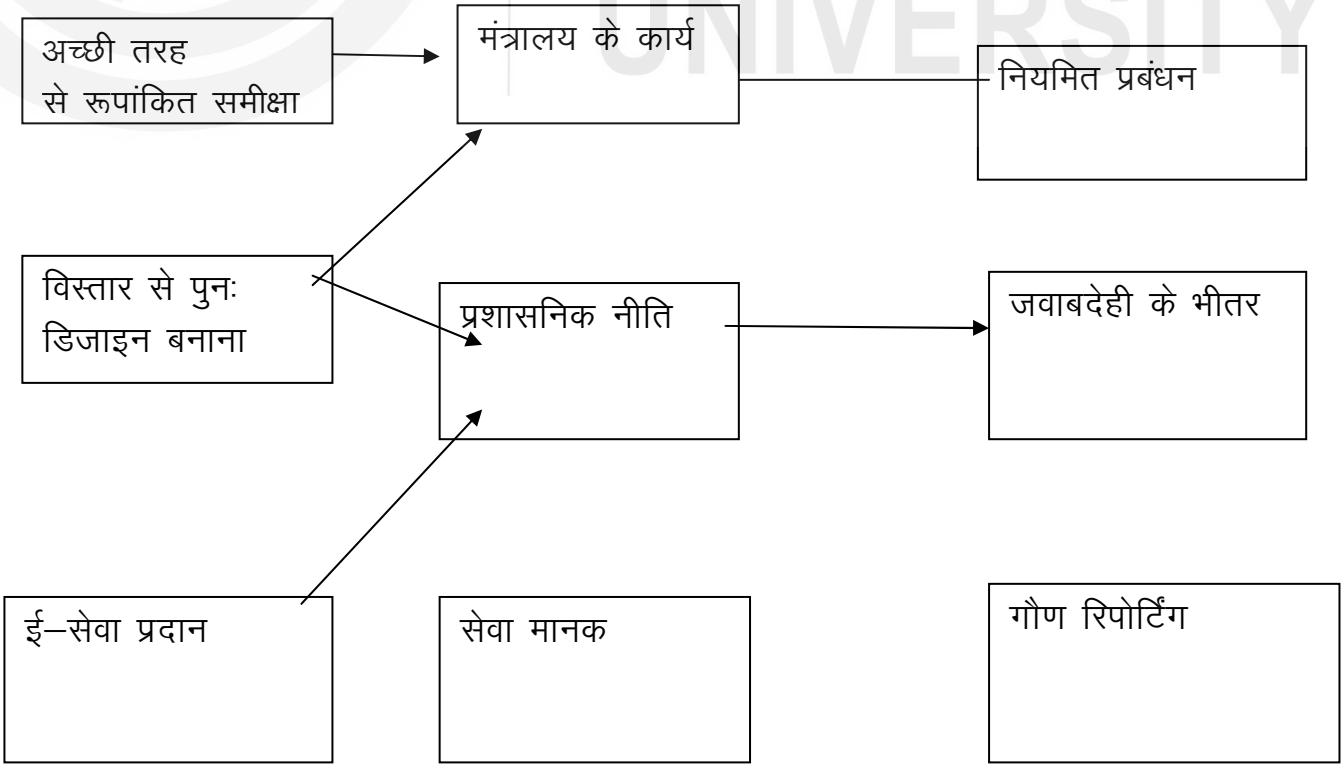

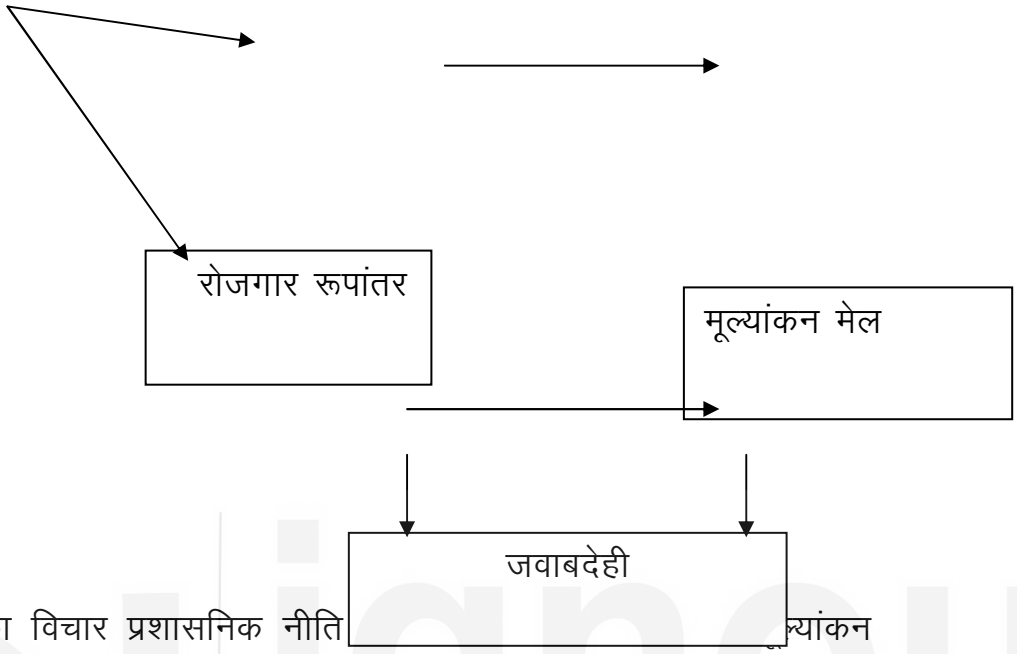


प्रशासनिक सुधारों का विचार प्रशासनिक नीति [redacted] ल्यांकन मेल–सेवा प्रदान, रोजगार रूपांतर, नियमित प्रबंधन जवाबदेही के भीतर और अच्छी तरह से रूपांकित की गई समीक्षा का प्रतीक है।

अन्य सुधार कार्यान्वयन प्रक्रिया पांच–छह वर्षों के दौरान आरंभ हुई। ये सुधार मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करते हैं :

1) रूसी संघ में लोकसेवा पुनर्गठन का मॉडल;

2) 2006–08 में रूसी संघ में प्रशासनिक पुनर्गठन का मॉडल; और

3) 2004–06 में रूसी संघ में बजट प्रक्रिया के पुनर्गठन का मॉडल।

**ई–रूस योजना**

रूस में एशिया संघीय कार्यक्रम स्थापित किया गया था और रूस के बजट नियंत्रण तंत्र में पारदर्शिता लाने के लिए ई–रूस योजना स्थापित करना चाहता था। इसे वर्ष 2002–2010 के दौरान सुधारों की प्रक्रिया में लागू किया था। ई–रूसी योजना के संबंध में, कई अंतरराष्ट्रीय संगठन राष्ट्रीय सुधारों की प्रक्रिया में लागू किया गया था। ई–रूसी योजना के संबंध में, कई अंतराष्ट्रीय संगठन राष्ट्रीय सुधारों की प्रक्रिया में लागू किया गया था। ई–रूसी योजना के संबंध में, कई अंतरराष्ट्रीय संगठन राष्ट्रीय सुधारों को बनाए रखने वाली परियोजनाओं और कार्य योजना के नेटवर्क से जोड़ने के लिए भी पहल कर रहे हैं। अन्य आंतरिक कारक हैं, जो रूस में सुधार के नकारात्मक प्रभाव का नेतृत्व कर रहे हैं। ये इस प्रकार है :

1) रूसी संघ में पदानुक्रम के शीर्ष पर प्रतिक्रिया का स्तर बहुत कम हैं;

2) विशेषज्ञ कर्मियों की कमी; और

3) लोक प्रबंधन पुनर्गठन एक पदानुक्रम प्रक्रिया है।

## 14.4 भारत में प्रशासनिक सुधार

प्राचीन सभ्यता के बाद से, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक जैसे सम्राटों और गुप्तवंश के नेताओं द्वारा प्रशासनिक सुधारों का एक क्रम चलाया गया। अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र और शुक्र–नीति जैसे प्रवचन प्रशासनिक सुधारों की क्षमता और ग्रहणशीलता को बल देने वाले मार्गदर्शक सिद्धांत से भरे हुए हैं। शास्त्रीय ग्रंथों के साथ ये प्रवचन प्राचीन भारत

में प्रशासनिक परिवर्तन लाए। परिवर्तन में शामिल है : विवरणियों का प्रशासन, स्थानीय शासन, व्यवसाय और कार्मिक। प्रशासनिक प्रणाली के विवरण को अभूतपूर्व माना जाता था। मौर्य प्रशासन ने जीवन के कृत्रिम और सम्मिलित विकास पर रूपांकित (डिजाइन) किया। भारत में मुस्लिम शासन ने अकबर, जहांगीर और शाहजहां के युग के दौरान उल्लेखनीय प्रशासनिक सुधार देखें। मुगल प्रशासन के प्रमुख उद्देश्य सत्ता का केंद्रीकरण, एक मजबूत नियंत्रित क्षेत्रीय प्रणाली, प्रशासक के बीच अधिकार का विस्तृत प्रभाव, एक कुशलता से प्रबंधित कृषि प्रणाली, विस्तृत न्यायिक और मजिस्ट्रेट पर्यवेक्षण, मजबूत मौद्रिक प्रबंधन, अच्छी तरह से एकीकृत राजस्व कागजी कार्रवाई, रोजगार का आधार योग्यता थे। यह उस समय की अवधि में अच्छी तरह से रूपांकित किए गए, जो प्रशासनिक सुधारों पर आधारित थे।

### *ब्रिटिश चरण (The British Phase)*

ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश क्राउन के समय, प्रशासनिक व्यवस्था में सुधारों की एक श्रृंखला आरंभ की गई थी, जिसका प्रभाव आज की प्रशासनिक व्यवस्था पर भी है। केंद्रीय सचिवालय का गठन, विभागीयकरण की व्यवस्था, जिला प्रशासन का सुदृढ़ीकरण, नगरीय स्थानीय सरकार का गठन, कानून के नियम का कार्यान्वयन, न्यायपालिका का सुधार, पुलिस सुधार, अखिल भारतीय सेवाओं का गठन, खुली प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा भर्ती, लोक सेवा आयोग का संगठन और सिविल सेवा प्रशिक्षण प्रमुख प्रशासनिक सुधार थे जिनका उल्लेख किया जा सकता हैं। सिविल सेवा में

विकासात्मक अभिविन्यास के विचार की नीवं ब्रिटिश चरण में थी, जिसने लगातार एक जवाबदेह सरकार के निरंतर विकास को देखा। कंपनी के शासन के समय, तत्कालीन गवर्नर जनरलों के प्रस्ताव पर कई प्रशासनिक परिवर्तन किए गए थे।

ब्रिटिश क्राउन (शासन) के समय, प्रशासनिक व्यवस्था में विकास के प्रस्ताव के लिए महत्वपूर्ण समितियों और आयोगों का गठन किया गया था। भारतीय सिविल सेवा (1854) सिविल सेवा वेतन पर विशेष समिति (1860) भारतीय सिविल सेवा के लिए उम्मीदवारों के चयन और प्रशिक्षण पर समिति (1876), लोक सेवा आयोग, (1886–87) विकेंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन (1907–09)। भारत में लोक सेवा पर रॉयल कमीशन महत्वपूर्ण समितियाँ है, जिसने देश में प्रशासनिक सुधार की दिशा में बहुत योगदान दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत सरकार सचिवालय विभागों के पुनर्गठन की स्थापना पर सुझााव देने के लिए रिचर्ड टोटेनहम को नियुक्त करना चाहती थी, और उसे कार्यकाल प्रणाली पर काम करने के लिए कहा। टोटेनहम ने दो रिपोर्टो का सुझाव दिया, एक 1945 में और दूसरा 1946 में। 1946 में पहला वेतन आयोग भी नियुक्त किया गया था और इसकी रिपोर्ट 1947 में प्रस्तुत करने के अधीन थी।

## *संविधान को अपनाना (Adoption of the Constitution)*

1950 में हमारे लोकतांत्रिक संविधान की प्रस्तावना के बाद से देश में प्रशासनिक बुराइयों/खामियों को दूर करने के लिए विभिन्न प्रशासनिक समितियों और आयोगों की स्थापना की गई है। भारत में प्रशासनिक संघवाद के संदर्भ में, भारत में राज्य के

प्रशासनिक सुधार केंद्रीय प्रस्तावों द्वारा अधिक प्रभावित हुए है। कई रिपोर्टों में प्रशासनिक प्रणाली को विशिष्ट तंत्र के मजबूत मापदंडों को देखा गया। आरंभ में, आंध्र प्रदेश सुधार समिति (1960), राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति (1963), केरल प्रशासनिक सुधार आयोग (1958) भारत में प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार के लिए प्रमुख महत्वपूर्ण समितियाँ थीं।

### *समितियाँ और आयोग (Committees and Commissions)*

भारत में प्रशासनिक सुधारों को लागू करने के लिए कई समितियों का गठन किया गया था। यह कुछ मुख्य पहलुओं पर आधारित था। सिविल सेवकों की वेतन संरचना, शहरी सरकार, ग्रामीण प्रशासन और भ्रष्टाचार की रोकथाम भारत में प्रशासनिक सुधारों का प्रमुख एजेंडा था। भारत में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (1966) ने सभी स्तरो पर प्रशासनिक व्यवस्था की समीक्षा की, दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग (Administrative Reforms Commission-ARC) वर्ष 2005 में स्थापित किया गया था। इसने कुछ मुद्दों की जांच की, जिन्हें वर्तमान परिदृश्य में नए रूप की आवश्यकता थी।

दो ARC के अतिरिक्त, देश में बड़े उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अन्य समितियों और आयोगों का गठन किया गया था।

इसके अतिरिक्त, सचिवालय की सत्ता के हस्तांतरण के लिए सचिवालय पुनर्गठन समिति का गठन किया गया था। इसने सचिवालय में तकनीकी परिवर्तनों पर ध्यान केंद्रित किया। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1948 में आर्थिक समिति का भी गठन किया

गया था। समिति का उद्देश्य प्रशासन के सुचारू कामकाज के लिए सरकारी खर्च की निगरानी करना था। प्रभावी शासन के लिए दो सारगर्भित खर्च की प्रस्तुत की गई, एक रिपोर्ट भारत में लोक प्रशासन से संबंधित है, और दूसरी राज्य उद्यमों के कुशल संचालन पर। ए डी गोरवाला (A. D. Gorwala) द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जिसमें सिविल सेवाओं में दक्षता और अनुशासन पर ध्यान केंद्रित किया गया था। पॉल एच. एप्पलबी (Paul H. Appleby) द्वारा भी भारत में लोक प्रशासन पर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। उन्होंने कार्य प्रक्रिया में सुधार और प्रशासनिक संगठन की क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए सुझाव दिया और समीक्षा की। सिविल सेवकों की तकनीकी प्रशासनिक विशेषज्ञता और कौशल की निगरानी के लिए नई दिल्ली में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना की गई थी। अशोक चंदा समिति की स्थापना वर्ष 1954 में की गई थी जिसने अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण की सिफारिश की थी।

रेलवे में व्यापक परिवर्तन करने के लिए रेलवे भ्रष्टाचार जांच समिति का भी गठन किया गया था। वर्ष 1956 में पॉल एप्पल बी द्वारा फिर से भारत का दौरा किया गया और सरकारी औद्योगिक और वाणिज्यिक उद्यमों के प्रशासन के विशेष संदर्भ के साथ भारत की प्रशासनिक प्रणाली की पुनः परीक्षा पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। लोक सेवाओं पर ए. आर. मुदलियार समिति भी स्थापित की गई थी। रिपोर्ट सिविल सेवाओं की भर्ती के लिए योग्यता से संबंधित है। इसके अतिरिक्त वर्ष 1957, 1959, 1962, 1964, 1966 में व्यापक सुधार प्रस्तावों को लागू किया गया। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की

भ्रष्टाचार निवारण, परिलब्धियां और सेवा की शर्तें जैसी समितियों ने सिविल सेवकों के लिए आचार संहिता लागू करने पर ध्यान केंद्रित किया।

प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग भी मोरारजी देसाई के नेतृत्व में स्थापित किया गया था। आयोग ने प्रशासन के विभिन्न पहलुओं पर 20 भागों में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें केंद्र–राज्य संबंध, योजना का तंत्र, नागरिकों के निवारण तंत्र और आर्थिक प्रशासन जैसे पहलू शामिल थे। वर्ष 1975 में, एल. पी. सिंह और एल. के. झा, (L. P. Singh and L. K. Jha) सरकार के प्रशासक के रूप में, प्रशासन की दक्षता में सुधार करने का सुझाव दिया। वर्ष 1976 में डी. एस. कोठारी (D. S. Kothari) ने अखिल भारतीय सेवाओं के लिए एकल परीक्षा की प्रणाली का सुझाव दिया। उसके बाद अशोक मेहता समिति ने दो स्तरीय पंचायती राज संस्था की सिफारिश की। अशोक मेहता (Ashok Mehta) समिति ने मंडल पंचायतों की स्थापना के लिए सुझाव दिया। इसके बाद, राष्ट्रीय पुलिस आयोग (National Police Commission-NPC) की स्थापना वर्ष 1977–80 के दौरान की गई थी और NPC की रिपोर्ट में कानून प्रवर्तन तंत्र के आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित किया। 1984 में आर. एस. सरकारिया (R. S. Sarkaria) के नेतृत्व में केंद्र राज्य संबंधों पर एक और समिति की स्थापना की गई, जिसने 1988 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसने अंतर राज्य परिषद (Inter-State Council, 1990) की स्थापना का सुझाव दिया। इसके अतिरिक्त प्रशासन के सुचारू संचालन के लिए कई वेतन आयोगों की भी स्थापना की गई। 2001 में व्यय सुधार आयोग की स्थापना की गई थी।

2005 में, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग स्थापित किया गया था, और इसने शासन के विभिन्न पहलुओं पर 15 रिपोर्ट प्रस्तुत की। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी प्रभावी शासन की कुंजी के रूप में सूचना के अधिकार पर जोर दिया। यह वीरप्पा मोइली के नेतृत्व में था जिसे भारतीय प्रशासन की अच्छी तरह से जाँच के लिए रूपरेखा दी गई थी। आयोग ने देश के लिए ग्रहणशील और सतत प्रभावी शासन को पूरा करने के उपायों की सिफारिश की। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने भारतीय प्रशासन के सुचारू संचालन के लिए अन्य सुझाव भी दिए।

2010 में केंद्र–राज्य संबंधों पर द्वितीय आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और सरकारिया आयोग (Sarkaria Commission) को कठोर बनाया। 2015 और 2016 के अंत में, शासन में प्रशासन पर विभिन्न पहले करने के लिए नीति आयोग की भी स्थापना की गई। वर्तमान सरकार मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया प्रोग्राम (कौशल भारत कार्यक्रम) जैसी विभिन्न विकासात्मक योजनाओं को लागू करके प्रशासन के सकारात्मक विकास पर भी पहल कर रही है। नीति आयोग की ओर से प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए सतत विकास लक्ष्यों को भी लागू किया गया है।

नीति आयोग की संचालन परिषद (Governing Council) की प्रथम बैठक 8 फरवरी 2015 को हुई। बैठक में प्रशासन के लिए विभिन्न विकास योजनाओं का सुझाव दिया

गया। इसके अतिरिक्त, सामाजिक क्षेत्र सेवा वितरण, 2015 में अच्छे व्यवहार पर संसाधन पुस्तक को पारित किया गया और भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया।

विषय वस्तु में शिक्षा और स्वास्थ्य पर प्रभावी शासन शामिल है। शासन में प्रशासनिक सुधारों के मिश्रित परिणाम मिले है लेकिन कुल मिलाकर ये सभी क्षेत्रों से बहुत सफल रहे हैं। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 भी लागू किया गया था और इसका उद्देश्य भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए लोकपाल की स्थापना की पेशकश करना था। वर्तमान सरकार प्रगति नामक एक मंच के माध्यम से सुधारों और विकास के कार्यान्वयन की निगरानी कर रही है। (सक्रिय सरकार और समय पर कार्यान्वयन)।

**बोध प्रश्न–1**

**टिप्पणी** : (i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

(ii) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर मिलाइए।

1) ब्राजील में उत्तर–नवलोक प्रबंधन सुधारों की चर्चा कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

2) ई–एशिया (रूस) योजना क्या है?

.....

.....

.....

.....

.....

3) भारत में प्रशासनिक सुधारों का परीक्षण कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

## 14.5 चीन में प्रशासनिक सुधार

चीनी सरकार ने 1980 के दशक के आरंभ से ही राजनीति, समाज और आर्थिक परिवर्तनों को एकत्र करने के लिए दीर्घकालिक प्रशासनिक सुधारों को सकारात्मक रूप से दबाया है। यह केवल शासन को बढ़ावा देने के लिए प्रभावशीलता के लिए था। चीन में प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा में निम्नलिखित शामिल हैं :

i) चीन में प्रशासनिक सुधार के लिए वर्तमान चुनौतियों पर ध्यान देना;

ii) पारंपरिक राज्य–केंद्रित मूलरूप के तहत महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधारों की जांच करना; और

iii) चीन में प्रशासनिक सुधार के लिए वैकल्पिक तंत्र की जाँच करना।

1980 के दशक के बाद सामाजिक परिधि, राजनीति, अर्थव्यवस्था और विचारधारा को पर्याप्त रूप से विविध स्तरों में बदल दिया गया है। यह एक मौलिक सामाजिक क्षेत्र का परिवर्तन था। चीनी प्रशासन व्यवस्था में विभिन्न परिवर्तन हुए। ये इस प्रकार हैं :

- विचारधारा
- आर्थिक प्रणाली
- सामाजिक व्यवस्था
- वैश्वीकरण

वर्ग संघर्ष और क्रांति की अवधारणा से लेकर आर्थिक विकास तक परिवर्तन आए। आर्थिक विकास में सरकार और जनता दोनों की भागीदारी होनी चाहिए। आर्थिक लोकतंत्र ने राजनीतिक लोकतंत्र का स्थान ले लिया। चीनी अर्थव्यवस्था से पहले केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था थी। राज्य की हस्तक्षेपवादी भूमिका की तानाशाही स्थिति अब अप्रचलित हो गई है। बाजार अब समय की बहुत जरूरत बन गया है। सामाजिक संरचना के संदर्भ में, चीनी समाज खुली सामाजिक गतिशीलता के अधीन

है। इसने लोक रोजगार के खुलेपन को प्रतिबंधित कर दिया है, जो सिविल सेवा और भर्ती से संबंधित है। अब चीन आधुनिक उद्योग विकसित करने में देखा जा रहा है। चीन में शहरीकरण और नगर नियोजन का तेजी से विकास हो रहा है। वैश्वीकरण के बाद, चीनी समाज अपनी अर्थव्यवस्थाओं को वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में एकीकृत करना चाहता था।

चीनी समाज के अत्यधिक दबाव के कारण चीन की प्रशासनिक व्यवस्था को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। इन्हें शासन में प्रमुख मुद्दों और चुनौतियों के रूप में पहचाना गया है।

- वैधता के मुद्दे;
- राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम मुद्दे;
- वित्तीय मुद्दे; और
- प्रशासनिक राज्य के मुद्दे।

वैधता संकट (Legitimacy crisis) के संदर्भ में, विश्वास के क्षेत्र को अस्वीकार कर दिया जाता है। बड़े पैमाने पर नौकरशाही भ्रष्टाचार था। राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम कम उत्पादन का सामना कर रहे थे। स्थानीय शासन से लेकर केंद्र प्रयोजित योजनाओं और शासन में मौद्रिक अभाव था। चीन के प्रशासनिक राज्य में भाई–भतीजावाद और निरंकुशता थी। जवाबदेही भ्रामक थी। इसे दिवंगत नेता देंग शियाओपिंग (Deng Xiaoping) ने मान्यता दी थी। ये समस्याएं और आपदा प्रत्येक

ऊंचाई पर अलग–अलग मात्रा में सरकार में सार्वभौमिक रूप से विद्यमान रही। विभिन्न समस्याओं की पृष्ठभूमि में, चीनी सरकार ने प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए प्रभावी सुधार करने का निर्णय लिया। चीन में आम आदमी के लिए प्रशासनिक सुधार लागू करने से ही सुशासन संभव होगा। कहा जाता है कि सरकार की बहुत सारी पेरशानियों और समस्याओं को समाप्त करने के लिए देश भर में चार गोल मेजों में बड़े पैमाने पर सरकारी संगठनात्मक सुधार (Government Organizational Reform-GOR) प्रचलित है। यह क्रमशः वर्ष 1982, 1988, 1992, 1998 में स्पष्ट था। सुधार ने *चार* विशिष्ट क्षेत्रों पर प्रकाश डालाः

i) सरकार के कार्यों में परिवर्तन;

ii) कर्मियों को छांटना;

iii) सरकार और उद्यम युक्तिकरण; और

iv) कानून के नियमों का संहिताकरण।

सरकार के कार्यों के क्रम पर, सरकार अब लोक वस्तुओं और सेवाओं के आवंटन जैसी सामाजिक पूंजी पर ध्यान दे रही है। चीन सैद्धांतिक रूप से सीमित सरकार चाहता था। चीनी अर्थव्यवस्था के समय की जरूरत यह है कि सरकार को विभिन्न संरचनाओं और मानदंडों के साथ समायोजित करना है। केंद्र सरकार के नियम 1998 के अनुसार, सरकारी संगठनात्मक सुधार ने विभागीय ढांचे को युक्तिसंगत बनाया। छोटी सरकार,

बड़े समाज के सिद्धांत का पालन किया गया। चीनी समाज योग्यता आधारित सिविल सेवा प्रणाली और कुशल उन्मुख सिविल सेवा के लिए खड़ा था। राजकोषीय दबाव के कारण, चीन सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के 50 प्रतिशत की कटौती करने का प्रस्ताव रखा। चीनी सरकार ने जानबूझकर व्यापार के विस्तार में नौकरशाही के तरीकों की उपेक्षा की। कानून के नियम चीन में प्रशासनिक शासन का आधार है। सरकारी–कर्मचारी की व्यवस्था पक्षपात से योग्यता आधारित व्यवस्था में बदलने लगी।

चीन में प्रशासनिक सुधार का लक्ष्य सरकारी दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ावा देना है। चीन में प्रशासनिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए मूल्य अभिविन्यास की बहुत आवश्यकता है, जिस पर मिनोब्रुक सम्मेलन में जोर दिया गया था। प्रशासनिक पुनर्गठन पूरे समाज के विस्तार को आगे बढ़ाने में सक्षम होना चाहिए। प्रशासनिक सुधारों से पहले संगठनात्मक पुनर्गठन के रूप में माना जाता था। वर्तमान में इसने सरकारी संगठन की कटौती और कर्मियों को युक्तिसंगत बनाने पर प्रकाश डाला।

***चीन में नागरिक केंद्र शासन प्रतिमान (Citizen Centre Governance Paradigm In China)***

चीन में नागरिक केंद्रित सरकार प्रतिमान विकसित किया गया था। यह प्रशासन में शासन की एक अभिनव रणनीति थी, जो सरकार को संस्थागत संवाद और समझौता मानती थी और विकेंद्रीकरण और स्थानीय शासन का दृढ़ता से समर्थन करती थी। यह

प्रतिमान को विकास, परिवर्तन और एकीकरण को बढ़ावा देने के क्षेत्र में भूमिका निभाने का अवसर देता हैं।

### *चीन में सरकार का पुनःनिर्माण (Reinventing Government in China)*

चीन में सरकार का पुनःनिर्माण करना संबंधों के पुनःनिर्माण के विरुद्ध एक अभियान है। सरकार और नागरिक, सरकार और उद्यम, केंद्र सरकार और स्थानीय सरकार के बीच संबंध को क्रमशः मजबूत किया जा रहा है। कार्यपालिका और विधायिका के बीच, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संबंधों आदि का भी पता लगाया जा रहा है।

### *विकेंद्रीकरण अभियान (Decentralization Drive)*

विकेंद्रीकरण अभियान ने राज्य–स्थानीय संबंधों में बड़े परिवर्तन को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। इसने वास्तविक वित्तीय संघवाद को बढ़ावा दिया। 1994 से एक नई अलग कर प्रणाली योजना को वैध बनाया गया था और स्थानीय शासन ने कराधान, निवेश और विधायी शक्तियों के संदर्भ में अधिक शक्तियां ग्रहण की हैं। वर्तमान में चीन में सरकार ने राज्य की आय कर सहभाजन प्रणाली को सुव्यवस्थित किया है।

### *सामुदायिक शासन (Community Governance)*

सामुदायिक शासन चीन में प्रशासनिक सुधारों के प्रमुख प्रतिमानों में से एक है। 1982 के संविधान ने स्थानीय स्व–शासन की अवधारणा को संहिताबद्ध किया। चीन में ग्रामीण ग्राम समितियाँ और शहरी पड़ोस समुदाय प्रचलित है। 1987 में, राष्ट्रीय जनता

कांग्रेस (NPC) ने चीन में इन समुदाय आधारित संगठनों के लिए दो ऐतिहासिक जैविक कानूनों को अपनाया। वर्तमान में कई गृहस्वामी संघ बड़े हो गए हैं और सामुदायिक शासन में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।

### *प्रशासनिक शक्तियों में कटौती (Curtailment of Adminsitrative Powers)*

मुख्य प्रशासनिक सुधार अत्यधिक और अति सक्रिय प्रशासनिक शक्तियों को कम करना है। यह सुधार वर्ष 2001 में आरंभ किया गया था। प्रशासनिक परीक्षा और अनुमोदन के सुधार पर अग्रणी समूह का गठन किया जाता था। 2003 में, लाइसेंस देने को मानकीकृत करने के लिए प्रशासनिक लाइसेंस देने के कानूनों को लागू किया। कानून यह प्रावधान करता है कि सरकार स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक सेवा केंद्रों को बढ़ावा देती है, ताकि लाइसेंस प्राप्त आवेदकों को कई सरकारी कार्यालयों में भुगतान किए बिना एक केंद्रीय कार्यालय में स्वीकृत उनके आवेदनों के करीब आने की अनुमति मिल सके। लेकिन 2013 के बाद से, प्रशासनिक समीक्षा और अनुमोदन शक्तियों से बचने के लिए प्रशासनिक सुधार को क्रियान्वित किया गया है। राज्य परिषद के संस्थागत पुनर्गठन और कार्यों के परिवर्तन की योजना एनपीसी द्वारा 2013 में लागू की गई थी।

### *बहुल शासन (Plural Governance)*

चीन के प्रशासनिक सुधार बहुल शासन को बढ़ावा देने के लिए है। सरकार ने सभी स्तरों पर मिश्रित शासन के मजबूत करने में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए नागरिक

समाज संगठनों जैसे कई राज्य और गैर–राज्य अभिनेताओं को आमंत्रित किया। सरकार सामाजिक प्रबंधन कार्यों के विचार–विमर्श में भाग लेने के लिए गैर सरकारी संगठनों को आमंत्रित करना चाहती थी। इन जमीनी संगठनों से सामाजिक सेवा योजना खरीदने के लिए सरकारी विभाग सक्रिय रूप से लगे हुए है।

### *लोक प्रशासन की कानून आधारित प्रणाली (Law Based system of Public Administration)*

अनेक प्रशासनिक कानूनों को राज्य परिषद द्वारा निष्पादित किया गया था और कानून बनाया गया था। इस कानून का उद्देश्य बाजार को सुगम बनाना हैं। राज्य परिषद ने प्रशासन के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने पर विचार प्रकाशित किए। इसका उद्देश्य उज्जवल सरकार को बढ़ावा देना है। प्रशासनिक मुकद्मेबाजी कानून का अधिनियमन था। इसे प्रकाशन की प्रभावशीलता में सुधार के लिए लागू किया गया था।

## 14.6 दक्षिण अफ्रीका में प्रशासनिक सुधार

1994 में दक्षिण अफ्रीका के लोकतांत्रिक शासन में राजनीतिक परिवर्तन ने महत्वाकांक्षी लोक क्षेत्र के सुधारों का मार्ग प्रशस्त किया, जिसने राज्य के संगठनात्मक और कार्मिक रूपरेखा के पुनर्गठन की मांग की। इस प्रक्रिया का एक प्रमुख उद्देश्य दूरगामी सामाजिक–आर्थिक नीति एजेंडा को चलाने के लिए राज्य की प्रबंधन क्षमता को बढ़ाना था, जो तुलनात्मक लोक प्रबंधन अभ्यास के सिद्धांतों और उपकरणों पर आधारित था क्योंकि यह विश्व स्तर पर और बौद्धिक रूप से विकसित हुआ था। दक्षिण अफ्रीका ने

शासन में व्यापक विकास किया है और लोक सेवा सुधार उपायों की स्थापना की है, इन कार्यान्वयन उपायों ने राजनीतिक क्षेत्र के प्रत्येक पहलू को स्पर्श किया है। सुधार प्रक्रिया सरकार की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायिक शाखाओं के क्षेत्र में सुधार आंदोलन के ऐतिहासिक पल के रूप में आरंभ हुई। सुधार ने शासन में नागरिक समाज संगठनों की भूमिका को भी शामिल किया। सुधार राजनीतिक कमरे के विकास के साथ अवरूद्ध नहीं हुए हैं, बल्कि लोक सेवा के नवीनीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए आगे बढ़े हैं। दक्षिण अफ्रीका के विकास के लिए नई भागीदारी (New Partnership for Africa's Development-NEPAD) भी दक्षिण अफ्रीका में सुधार की रणनीति थी।

### *लोक सेवा सुधार (Public Service Reform)*

हाल के वर्षों में, अफ्रीकी सरकारों ने लोक सेवा के पुनर्गठन पर विचार किया है। लोक सेवा सुधार हाल के दिनों में विकसित हुए हैं। सुधार के निम्नलिखित उद्देश्यों पर नीचे चर्चा की गई हैं :

- श्रम पुनर्वितरण और बेरोजगारी;
- ग्राहक–देखभाल पहल की प्रस्तावना;
- अभिलेखों और सूचना प्रशासन प्रणालियों का विकास;
- स्थानीय सरकार और विकेंद्रीकृत एजेंसियों का पुनरोद्धार; और
- भ्रष्टाचार विरोधी उपायों की उपलब्धि।

## संघर्ष के बाद के माहौल में सुधार

1991–92 के सुधारों के हिस्से के रूप में राजनीतिक अधिकारों का विस्तार किया गया। इसने एक बहुदलीय प्रणाली देखी और संघ की स्वतंत्रता का आश्वासन दिया। 1991–92 के संवैधानिक सुधारों ने राजनीतिक बहुलवाद की बात की और नागरिकों के मूल अधिकारों की पेशकश की।

दक्षिण अफ्रीका में सरकार ने ''Programmea De Reforma Institutrement e Moderniza o Administration (PRIMA)'' के माध्यम से शासन के कई मुद्दों से निपटने के लिए कदम उठाए, जिसे वर्ष 1996 से लागू किया गया था। दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए :

i) सिविल सेवक पदों का पुनर्गठन; और

ii) आधुनिक मानव संसाधन प्रबंधन का उद्घाटन।

वर्ष 1999 में, दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने ''प्रशासनिक सुधार कार्यक्रम'' (Programme De Reforma Adminstrativa - PREA) नामक एक अभिनव कार्यक्रम शुरू किया। कार्यक्रम का उद्देश्य लोक प्रशासन को अधिक उत्तरदायी और वैध बनाना है। सरकार ने सिविल सेवा को कम करने और उसमें कटौती करने के लिए कदम उठाए हैं। यह स्पष्ट है कि शीघ्र सेवानिवृति पैकेज स्वीकार कर लिया गया और सेवा छोड़ दी गई। आगे का विवाद वेतनमान बढ़ाने को लेकर है।

PREA के सुधारों की मूल विशेषताएं नीचे उल्लिखित है :

i) लोक प्रशासन की संस्थागत और प्रबंधन योग्यता;

ii) गैर–नौकरशाही का विकास और लोक प्रशासन की मान्यता/पुष्टि;

iii) स्थानीय स्तर पर शक्तियों के विकेंद्रीकरण और संकेद्रण पर जोर;

iv) जमीनी स्तर पर राजकोषीय प्रशासन का आधुनिकीकरण;

v) प्रभावी सेवा वितरण प्रणाली; और

vi) नागरिक समाज की भागीदारी को प्रोत्साहन।

सूचना प्रबंधन भी दक्षिण अफ्रीका में सुधार प्रक्रिया का एक अन्य तरीका है। संसाधन प्रबंधन और पारदर्शिता सुधार की प्रक्रिया में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, कई द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दाताओं ने कई पहले की है। बाहरी दाताओं, विशेष रूप से इटली ने, GEPE MAPESS और INAP की देखरेख में निष्पादित एक कार्यक्रम सहायक दस्तावेज (Program Support Document-PSD) का वित्त पोषण किया।

''Reforco Institutional De Administracao Public (REFORPA)'' नामक अभिनव कार्यक्रम तीन विशेषताओं से बना है।

- प्रशिक्षण केंद्रों का नेटवर्क;

- तकनीकी सहायता सुविधा;
- स्थानीय और केंद्र सरकार के लिए प्रशासन और प्रबंधन पाठ्यक्रम की व्यवस्था;
- तकनीकी सहायता सुविधा; और
- प्रबंधन और सेवा वितरण प्रणाली।

मोजाम्बिक (Mozambique) एक और देश है जो सुधार के मामले में कल्पित (counterfeit) है। अर्थव्यवस्था हाल ही के वर्षों में उच्च गुणवत्ता वाली प्रगति का निर्माण कर रही है। सकल घरेलू उत्पाद 1990 में 2,463 मिलियन डॉलर से बढ़कर 2001 के 3,607 मिलियन डॉलर हो गया है, 2001 में वार्षिक विकास दर 13.9 प्रतिशत तक पहुंच गई है। इसने सरकर के गरीबी कम करने के प्रयासों पर पूर्ण रूप से प्रभाव डाला है।

2000 से, सरकार ने एक समावेशी लोक क्षेत्र सुधार रणनीति (Public Sector Reform Strategy-PSRS) के निर्माण के लिए दानकर्ता के रूप में सहारा देने की पहल की। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रक्रिया और अवलोकन को बदलना है। यह गरीबी उन्मूलन रणनीति के तहत निर्धारित सामाजिक–आर्थिक विस्तार और गरीबी में कमी करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लोक क्षेत्र की योग्यता को बढ़ा रहा है। सुधार प्रक्रिया को तैयार करने और चलाने में सहायता करने और पाठ्यक्रम तक देनकर्ता के रूप में सहारा देने की व्यवस्था की गई है। सरकार ने वर्ष 2000 में लोक क्षेत्र के सुधार के लिए व्यावहारिक इकाई UTRESP को मान्यता दी।

## *लोक क्षेत्र की सुधार कार्यनीति (**Public Sector Reform Strategy**)*

सार्जनिक क्षेत्र के सुधार को वर्ष 2000 में लागू किया गया था। इसे देनकर्ता देशों से समर्थन मिला। इसे व्यापक लोक क्षेत्र सुधार रणनीति कहा जाता था। सुधार का उद्देश्य सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन और गरीबी में कमी के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लोक क्षेत्र की प्रभावशीलता को बढ़ावा देना था। PAPRA को अभिनव गरीबी उन्मूलन रणनीति के रूप में लागू किया गया था। UTRESP एक अन्य तकनीकी इकाई थी जिसे 2000 में लोक क्षेत्र को प्रशासनिक सहायता प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था। इसकी अध्यक्षता मंत्रिस्तरीय समिति द्वारा की गई। विश्व बैंक ने भी उक्त उद्देश्य के लिए अनुदान के माध्यम से सहायता की जो वर्ष 2003 में स्पष्ट उल्लेखित था।

लोक क्षेत्र के प्रशासन में विकासात्मक रणनीति में निम्नलिखित प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख किया गया है:

i) हस्तांतरण और संस्थागत फेरबदल के माध्यम से सेवा वितरण को सभ्य बनाना;

ii) नीति निर्माण और निगरानी विकास और योग्यता में गहनता;

iii) लोक क्षेत्र में आकर्षक व्यावसायिकता;

iv) वित्तीय प्रबंधन और जवाबदेही में सुधार;

v) सुशासन को प्रोत्साहित करना और भ्रष्टाचार से लड़ना; और

vi) परिवर्तन प्रक्रिया का प्रशासन (पर्यवेक्षण परिवर्तन)।

लोक सेवा के लिए अफ्रीकी चार्टर को कैमरून में विकासात्मक योजनाओं की प्रथाओं के लिए लागू किया गया था। उपभोक्ताओं को कंप्यूटर संदर्भ संख्या देने के लिए ICT पर नई सेवा वितरण प्रणाली तैयार की गई थी। सरकार दक्षिण अफ्रीका में कई प्रशासनिक सुधार उपायों के कदम उठा रही थी जिनकी चर्चा नीचे की गई है:

- राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी योजना का कार्यान्वयन;
- तदर्थ भ्रष्टाचार विरोधी समिति का कार्यान्वयन; और
- नागरिक समाज कार्यकर्त्ताओं को शामिल करना।

तंजानिया (Tanzania) में अफ्रीकी लोक सेवा चार्टर भी लागू किया गया था। यह लोक नैतिकता और जवाबदेही को मजबूत करने में प्रोत्साहित करता है। चार्टर ने 2001 में नैतिकता का मूल ढांचा भी प्रदान किया। दक्षिण अफ्रीका में सरकार ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 2002 का लोक सेवा अधिनियम और अफ्रीका में प्रशासन के सुचारू कामकाज के लिए संयुक्त बातचीत मशीनरी (तंत्र) अधिनियम भी बनाया।

कई भ्रष्टाचार विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रपति कार्यालय में एक सुशासन इकाई की स्थापना की गई थी। 1990 में सरकार ने नामीबिया में लोक सेवा आयोग अधिनियम का समर्थन किया, जिसने आयोग को लोक सेवा भर्ती, पारिश्रमिक,

विनियमन, प्रस्तुति और तरीके के विषय पर राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए अधिकृत किया।

1990 का लोकपाल अधिनियम चट्टान जैसे कठोर सिद्धांतों के संचार के निर्माण के लिए नामीबिया सरकार के संकल्प का एक और प्रमाण है। लोक सेवा आचार संहिता ने लोक सेवकों के लिए आचरण की एक समान प्रथा स्थापित की।

भ्रष्टाचार के मामलों के बारे में जांच–पड़ताल करने के लिए भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम 2003 भी बनाया गया था। दक्षिण अफ्रीका ने अफ्रीका में लोक सेवा आधुनिकीकरण में सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक इसे दर्ज किया है। बाथो पेले पर एक नारा था जिसका अर्थ है पहले जनता। लोक सेवा ने नागरिकों और गैर–नागरिकों की जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से प्रस्तावों का वर्गीकरण निष्पादित किया है। लोक सेवा और प्रशासन विभाग द्वारा प्रकाशित लोक सेवाओं की निर्देशिका दक्षिण अफ्रीकियों की भलाई के लिए सरकार की चिंता का एक संकेत है। दक्षिण अफ्रीका और इस क्षेत्र के अन्य देशों जैसे देशों में विकेंद्रीकरण के माध्यम से फल–फूल रहा है; जैसे युगांडा, रवांडा, नामीबिया और इथियोपिया।

दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने हाल के वर्षों में कई कदम उठाए हैं जैसे :

- अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की शक्तियों के साथ एक भ्रष्टाचार विरोधी निकाय का उद्यम;

- मानवाधिकारों पर एक उच्चाधिकार प्राप्त आयोग का संगठन;
- महालेखापरीक्षक के कार्यालय की गहनता;
- लोक सेवा सुधार कार्यक्रम की उपलब्धि;
- प्रस्तुतिकरण मूल्यांकन उपकरण का सुधार;
- सिविल सेवा परीक्षाओं की प्रस्तावना;
- प्रारंभिक प्रशिक्षण कक्षाओं का संघ और अन्य मानव योग्यता संरचना योजना; और
- संग्रह और सूचना प्रबंधन प्रणाली का विकास।

उपरोक्त सुधारों के अतिरिक्त दक्षिणी अफ्रीकी सरकार ने विविध दृष्टिकोणों से प्रशासन में सुधार किया हैः

- योग्यता आधारित सिविल सेवा प्रणाली का कार्यान्वयन;
- सामरिक मानव संसाधन प्रबंधन में निवेश वृद्धि;
- लोक सेवा में श्रम व्यवहार और बहुलता प्रबंधन का विकास करना;
- मानव संसाधन प्रबंधन सुधार के लिए अच्छी तरह से निर्मित मार्गदर्शन दायित्व; और
- मानव संसाधन प्रबंधन सुधार के लिए समग्र सोच को ग्रहण करना।

**बोध प्रश्न–2**

**टिप्पणी** : (i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

(ii) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर मिलाइए।

1) चीन में प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता की विवेचना कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

2) दक्षिण अफ्रीका में लोक क्षेत्र के सुधारों की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए?

.....

.....

.....

.....

.....

## 14.7 निष्कर्ष

ब्रिक्स में शासन में प्रशासनिक सुधार एक ऐसा पाठ्यक्रम है, जो अपने आवंटित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक प्रशासनिक प्रणाली की योग्यता में वृद्धि करता है। यह

लड़ाई के विरुद्ध प्रशासनिक परिवर्तन के कृत्रिम प्रोत्साहन में तल्लीन है। एक प्रणाली के पुनर्गठन के लिए उसके रूप में संशोधन की आवश्यकता होती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि संगठनात्मक सुधार एक प्रणाली में केवल संरचनात्मक संशोधन से संबंधित है। यह बहुत व्यापक क्षमता है और इसकी शासन क्षेत्र वृद्धि में प्रशासनिक प्रणाली और इसके तंत्र की संरचना, प्रगति और व्यवहार शामिल है। ब्रिक्स में प्रशासनिक सुधारों का उपक्रम सफलताओं और विफलताओं का मिश्रण रहा है। सरकार के समर्थन से समुदाय आधारित की भागीदारी को निष्पादन और कार्यान्वयन के क्षेत्र में लोक नीतियों को बढ़ावा देना चाहिए। प्रारंभ में, अधिकांश ब्रिक्स देशों ने जनता के समर्थन में संकटकाल प्रबंधन योजनाओं को बहुत ही ईमानदारी से लागू करने का इरादा किया है।

## 14.8 शब्दावली

**डिक्री कानून (Decree law)** : डिक्री (आज्ञा) कानून उस कानून को संदर्भित करता है जिसे राज्य के प्रमुख द्वारा अनुमादित किया जाता है।

**DFID** : अंतरराष्ट्रीय विकास विभाग (Deparment for International Development - DFID) यूनाइटेड किंगडम का एक सरकारी

विभाग है जो विदेशी सहायता से प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है।

**परिधि (Periphery)** : यह बताती है कि प्रमुख मुख्य क्षेत्रों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक शक्ति कैसे बिखरी हुई है।

**निरंकुशता (Despotism)** : पूर्ण शक्ति के प्रयोग को संदर्भित करता है।

## 14.9 संदर्भ लेख


Arora, R.K. & Goyal, R. (2013). *Indian Administration.* New Delhi, India: New Age International (P) LTD.

Balogun, M.J. & Mutahaba, G. (2015). *Redynamizing the Civil Service for The 21 Century:* Prospects for a Non-Bureaucratic Structure. *African Journal of Public Administration and Management.* 11(2).

Dodoo, R. (2015). *The Core Elements of Civil Service Reform.* African Journal of Public Administration and Management. 5-7(2).

Konn, T., Holzer, M. & Zhang, M. (2016). New Public Administration: Seeking Social Justice and Democratic Value. *The Journal of Chinese Public, Administration*. 1(2), 214-227.

Lodge, M. & Gill, D. (2011). Toward a New Era of Administrative Reform, The Myth of Post-NPM in Brazil Governance. *Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions*. 24(1), 141-166.

Parison, N. (2000). *ECSPE, Russia: Public Administration Reform: Issues and Options*.

Conference on Post-Election Strategy Moscow: The World Bank.


## 14.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

**बोध प्रश्न 1**

1) आपके उत्तर में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए :

भाग 14.2 देखिए।

2) आपके उत्तर में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए :

- रूस में संघीय कार्यक्रम स्थापित किया गया था और ई–रूस योजना स्थापित करना चाहता था।
- यह रूस के बजट नियंत्रण तंत्र में पारदर्शिता लाता है।
- इसे वर्ष 2002–2010 के दौरान सुधारों की प्रक्रिया में लागू किया गया था।

3) भाग 14.4 देखिए।

**बोध प्रश्न 2**

1) आपके उत्तर में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए :

भाग 14.5 देखिए।

2) आपके उत्तर में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए :

- हस्तांतरण और संस्थागत फेरबदल के माध्यम से सेवा वितरण को सभ्य बनाना
- नीति निर्माण और निगरानी विकास और योग्यता में गहनता

- लोक क्षेत्र में आकर्षक व्यावसायिकता
- वित्तीय प्रबंधन और जवाबदेही में सुधार
- सुशासन को बढ़ावा देना और भ्रष्टाचार से लड़ना।

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

## सुझाई गई पठन साम्रगी (Suggested Readings)


An Introduction to Parliament of India. (2007). Retrieved from https://rajyasabha.nic.in/rsnew/Parliament_of_India.pdf

Bhattacharya, M. (2008). *New Horizons of Public Administration*. New Delhi, India: Jawahar Publications.

Brasila Documentation and Information Center. (3rd ed.).(2010). Constitution of the Federative Republic of Brazil. Retrieved from https://www.globalhealthrights.org/wp-content/uploads/2013/09/Brazil-constitution-English.pdf

Chakrabarty, B. & Pandey, R.K. (2019). *Local Governance in India*. New Delhi, India: Sage.

Constitution of the People's Republic of China. Retrieved from http://www.npc.gov.cn/zgrdw/englishnpc/Constitution/node_2825.htm

Government of India. (1966). *Administrative Reforms Commission, Interim Report: Problems of Redress of Citizens Grievances*. Retrieved from https://www.darpg.gov.in/sites/default/files/01_ARC_Interim_Report07162019124141.pdf

Government of India. (1968). *Administrative Reforms Commission, Machinery for Planning.Retrieved from* https://www.darpg.gov.in/sites/default/files/02_Machinery%20for%20Planning07032019173216.pdf

Government of India. (1969). *Administrative Reforms Commission, State Administration.* Retrieved from https://www.darpg.gov.in/sites/default/files/14_On%20State%20Administration07052019120548.pdf

Government of India. (2007). *Second Administrative Reforms Commission (4th Report),Ethics in Governance.* Retrieved from https://www.darpg.gov.in/sites/default/files/ethics4.pdf

Government of India. (2007). *Second Administrative Reforms Commission (6th Report), LocalGovernance.* Retrieved from https://www.darpg.gov.in/sites/default/files/local_governance6.pdf

Government of India. (2009). *Second Administrative Reforms Commission (12th Report) Citizen Centric Administration.* Retrieved from https://www.darpg.gov.in/sites/default/files/ccadmin12.pdf

Government of India. (2009). *Second Administrative Reforms Commission (15th Report), State and District Administration.* Retrieved fromhttps://www.darpg.gov.in/sites/default/files/sdadmin15.pdf

Government of India. (2010). *Report of the Commission on Centre-State Relations (Vol-I),Evolution of Centre-State Relations in India.* Retrieved from http://www.interstatecouncil.nic.in/wp-content/uploads/2015/06/volume1.pdf

Government of India. (2010). *Report of the Commission on Centre-State Relations (Vol-IV),Local Self Governments and Decentralized Governance.* Retrieved from http://www.interstatecouncil.nic.in/wp-content/uploads/2015/06/volume4.pdf

Government of India. (2019). *Economic Survey Volume I & II, 2018-19*. New Delhi, India:Oxford University Press.

Jha, G. (2018). *Fragile Urban Governance.* New Delhi, India: Manohar.

Mani, N. (2016). *Smart Cities and Urban Development in India.* New Delhi, India: New Century Publications.

Mathew, G. (Ed.). (2013*). Status of Panchayati Raj in the States and Union Territories of India.* New Delhi, India: Concept Publishing Company.

Mathur, K. (2013). *Panchayati Raj.* New Delhi, India: Oxford University Press.

Mathur, K. (2019). *Recasting Public Administration in India: Reform, Rhetoric and Neoliberalism.* New Delhi, India: Oxford University Press.

Mohanty, P.K. (2014). *Cities and Public Policy: An Urban Agenda for India*. New Delhi, India: Sage Publications India Pvt. Ltd.

Overview of the Judicial System of the Russian Federation. Retrieved from http://www.supcourt.ru/en/judicial_system/overview/

Pal, M. (2020). *Rural Local Governance and Development*. New Delhi, India: Sage Publications India Pvt. Ltd.

Rosenn, K.S. (2009). Separation of Powers in Brazil. Retrieved from https://core.ac.uk/download/pdf/214392703.pdf

Sapru, R. (2017). *Public Policy: A Contemporary Perspective*. New Delhi: Sage Publications India Pvt. Ltd.

Sapru, R. (2018). *Indian Administration: A Foundation of Governance*. New Delhi, India: Sage Publications India Pvt. Ltd.

State Institutions (China). Retrieved from http://www.npc.gov.cn/englishnpc/statestructure2019/201911/fa2deebf75264effa68df01cfecfb60c.shtml

South African Government System. Retrieved from https://www.gov.za/about-government/government-system

The Constitution of the Russian Federation. Retrieved from http://www.constitution.ru/en/10003000-01.htm

The Constitution of India. Retrieved from https://legislative.gov.in/sites/default/files/COI.pdf

The Constitution of the Republic of South Africa, 1996. Retrieved from https://www.justice.gov.za/legislation/constitution/saconstitution-web-eng.pdf

Upadhyay, D. (Ed.). (2019). *The Handbook of Indian Judiciary: Development of Law, Struggle & Change.* New Delhi, India: Integrity Media.

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY